नई दिल्ली

04 जुलाई, 2026 शनिवार

मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 94

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

RNI No. DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com

Email : timesofpedia@gmail.com

नॉकआउट मैच जितने के बाद रोनाल्डो का इमोशनल सेलिब्रेशन वायरल 07

संक्षिप्त वार्ता

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने दिया इस्तीफा

इन्दौर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। करीब 30 साल तक पार्टी में विभिन्न पदों पर रह कांग्रेस का झंडा उठाने वाले मुखर कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने पार्टी छोड़ते ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी, यही नहीं उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साध उन्हें धृतराष्ट्र बताया है।

यादव ने कहा कि कांग्रेस में अब लोकतंत्र नहीं, बल्कि तानाशाही चल रही है। सच बोलने वालों को नोटिस देकर चुप कराया जा रहा है, जबकि संगठन कुछ नेताओं की मनमर्जी से संचालित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा चुनाव की हार के लिए जीतू पटवारी और हरीश चौधरी जिम्मेदार हैं। यादव ने यह भी आरोप लगाया कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के योग्य नहीं हैं, वरिष्ठ नेताओं का अपमान करते हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस अगले 15 वर्षों तक सत्ता में नहीं लौट पाएगी। टिकट वितरण और संगठन संचालन को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए।

टोल प्लाजा के पास एलपीजी टैंकर में लगी आग, चार की मौत, दो घायल

वेब वार्ता, लखनऊ। यूपी के कौशाम्बी ज़िले में एक टोल प्लाजा के पास एलपीजी टैंकर में आग लगने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज में वह भयानक पल कैद हुआ जब कौशाम्बी जिले के सिरोही टोल प्लाजा पर एलपीजी टैंकर से तेजी से गैस लीक होने लगी और कुछ ही सेकंड में वह आग का गोला बन गया। 26 जून 2026 के इस वीडियो में टैंकर से तेजी से सफेद गैस निकलती हुई दिखाई दी, जिसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी आग की लपटों में घिर गई, जिससे टोल बूथ वाले इलाके में आग फैल गई।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आग में 16 बाइकें और दो कारें जलकर खाक हो गईं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यह घटना तब हुई जब कानपुर से वाराणसी जा रहा एक एलपीजी टैंकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे भीषण आग लग गई। पुलिस ने बताया कि टक्कर के बाद गैस लीक हुई और टैंकर में आग लगने से पहले ही यह गैस तेजी से फैल गई, जिससे आसपास का इलाका आग की लपटों में घिर गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आग लगने से कुछ पल पहले तेज रफ़्तार टैंकर डिवाइडर से टकराता हुआ दिख रहा है।

जम्मू से 4822 शिव भक्तों का पहला जत्था रवाना

वेब वार्ता, जम्मू। भक्तों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ, क्योंकि पवित्र अमरनाथ यात्रा आज से आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने लगभग 4822 शिव भक्तों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुबह, पूजा-अर्चना और पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में वाहनों का पहला काफिला पवित्र गुफा की ओर बढ़ा। उप-राज्यपाल ने सभी यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सकुशल यात्रा की प्रार्थना की। उन्होंने अमरनाथ यात्रा को भक्ति और आध्यात्मिक जागृति का एक पवित्र मार्ग बताया, सभी भक्तों के लिए सुरक्षित, आरामदायक और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक यात्रा की कामना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह तीर्थयात्रा सभी के लिए अपार खुशी और दिव्य शांति लाएगी।

इस वार्षिक तीर्थयात्रा के सुचारु संचालन के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों, स्थानीय लोगों और सभी हितधारकों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पहले जत्थे में 4822 से अधिक तीर्थयात्री 259 हल्के और भारी वाहनों के काफिले में रवाना हुए। इस अवसर पर आयोजित समारोह में सांसद जुगल किशोर शर्मा, विधायक देवयानी राणा, विधायक अरविंद गुप्ता, आध्यात्मिक नेताओं, धार्मिक संगठनों के प्रमुखों, नागरिक प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

भगवती नगर बेस कैंप का माहौल भक्तिमय

भगवती नगर बेस कैंप में पूरा माहौल भक्तिमय था। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले, तीर्थयात्री बम बम भोले, हर हर महादेव और जय बफार्नी बाबा की के जयकारों से वातावरण गुंजा रहे थे। कई यात्रियों ने यात्रा के सुचारु और शांतिपूर्ण संचालन के लिए की गई व्यवस्थाओं पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया। उपराज्यपाल द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किए गए इस जत्थे के साथ, गुरुवार से अब तक कुल 8,687 तीर्थयात्री जम्मू बेस कैंप से घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं, जो इस पवित्र यात्रा के प्रति भक्तों के अटूट विश्वास और उत्साह को दर्शाता है। अधिकारियों ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और सभी ट्रांजिट कैंपों में कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है, ताकि यात्रा के काफिले की सुरक्षित और सुचारु आवाजाही बनी रहे। वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए भगवती नगर बेस कैंप और उसके आसपास भी बहु-स्तरीय सुरक्षा घेरा लागू किया गया है, जो किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार है।

पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं को लिखा पत्र

नई दिल्ली। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के श्रद्धालुओं के नाम एक विशेष पत्र लिखकर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बाबा बफार्नी के दर्शन हर शिवभक्त के लिए सौभाग्य का विषय हैं और यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित यात्रा करने, पर्यावरण की रक्षा करने और स्थानीय लोगों का सहयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने पांच महत्वपूर्ण संकल्प लेने का भी आग्रह किया, ताकि यह यात्रा आस्था के साथ-साथ सेवा और राष्ट्र निर्माण का संदेश भी दे सके।

प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर प्रथम पूजा के साथ ही बाबा अमरनाथ के दर्शन का पावन क्रम शुरू हो जाता है और देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि अमरनाथ धाम की यात्रा आध्यात्मिक ऊर्जा देने के साथ-साथ भारत की विविधता में एकता की भावना को भी मजबूत करती है। अलग-अलग राज्यों, भाषाओं और परंपराओं से जुड़े लोग एक ही आस्था के साथ बाबा बफार्नी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री ने यात्रा के सफल संचालन के लिए श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड, जम्मू-कश्मीर प्रशासन, भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के योगदान की भी सराहना की।

200 साल पुराने मंदिर के तीनों शिखर बिजली गिरने से ध्वस्त

वेब वार्ता, रतलाम

जिले के शिवगढ़ क्षेत्र के ग्राम चौरानी में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने भगवान लक्ष्मीनारायण एवं राम मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। तेज गर्जना के साथ गिरी बिजली से मंदिर के तीनों शिखर पूरी तरह ध्वस्त हो गए और मलबा चारों ओर बिखर गया। घटना के समय हुए तेज धमाके की आवाज करीब तीन किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के गांवों में दहशत फैल गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिजली इतनी तेज थी कि कुछ ही क्षणों में मंदिर के शिखर ढह गए। आसपास के मकानों और खेतों तक कंपन महसूस किया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना के समय मंदिर परिसर में कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा नुकसान का जायजा लिया। मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को देखते हुए इसके पुनर्निर्माण की मांग उठने लगी है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है, जबकि ग्रामीण इसे दुर्लभ प्राकृतिक घटना मान रहे हैं।

जुलाई में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, आरबीआई ने जारी की छुट्टियों की सूची

वेब वार्ता, मुंबई

जुलाई की शुरूआत के साथ ही बैंक से जुड़े जरूरी काम करने वाले ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी बैंक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, जुलाई महीने में देश के विभिन्न राज्यों में बैंक कुल 11 दिन बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में चार रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार तथा अलग-अलग राज्यों के क्षेत्रीय त्योहार शामिल हैं। हालांकि, ये सभी छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगी। अधिकांश अवकाश स्थानीय त्योहारों और क्षेत्रीय आयोजनों से जुड़े हैं, इसलिए केवल संबंधित राज्यों में ही बैंक बंद रहेंगे। देशभर में ऐसा कोई दिन नहीं है, जब किसी त्योहार के कारण सभी राज्यों के बैंक एक साथ बंद रहेंगे।

महाराष्ट्र के ग्राहकों के लिए राहत

महाराष्ट्र के बैंक ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि साप्ताहिक अवकाश (शनिवार और रविवार) के अलावा जुलाई में कोई अतिरिक्त बैंक अवकाश नहीं है। यानी राज्य में बैंक सामान्य दिनों में नियमित रूप से खुले रहेंगे और बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी।

जुलाई में बैंक कब-कब रहेंगे बंद?

- 5 जुलाई- रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
- 6 जुलाई- मुहर्रम (आशूरा) के अवसर पर कई राज्यों में बैंक बंद
- 9 जुलाई- मेघालय में बेह दिंखलाम पर्व
- 11 जुलाई- दूसरा शनिवार
- 12 जुलाई- रविवार
- 16 जुलाई- ओडिशा और मणिपुर में रथ यात्रा
- 17 जुलाई- मेघालय में यू तिरोट सिंग की पुण्यतिथि
- 19 जुलाई- रविवार
- 22 जुलाई- त्रिपुरा में खर्ची पूजा
- 25 जुलाई- चौथा शनिवार
- 26 जुलाई- रविवार

डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम और अन्य डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक ऑनलाइन पैसे भेजने, बिल भुगतान, बैलेंस चेक करने और अन्य डिजिटल लेनदेन आसानी से कर सकेंगे।

जरूरी काम पहले ही निपटा लें

यदि आपको चेक जमा करना, नकद जमा या निकासी, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना या बैंक शाखा में जाकर कोई आवश्यक कार्य करना है, तो छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए पहले से योजना बनाना बेहतर होगा। इससे अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।

बागेश्वर धाम पहुंचे अनंत अंबानी, पूजा-अर्चना की, हाथ में थामी गदा

नई दिल्ली,। देश के जाने-माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने बागेश्वर धाम पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने पूजा-अर्चना की। इस दौरान वह धीरेंद्र शास्त्री के साथ पूजा में शामिल हुए। एक वीडियो में अनंत को धीरेंद्र शास्त्री के साथ हाथ में गदा थामे देखा गया। धीरेंद्र शास्त्री मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी हैं, वह कथा सुनाते हैं।

बता दें कुछ दिन पहले अनंत अंबानी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए थे। इस दौरान उन्होंने वहां की सालों पुरानी धार्मिक परंपरा का पालन करते हुए अपने केश भी दान किए। तिरुमला में केश दान को धार्मिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। श्रद्धालु केश दान को भगवान के प्रति श्रद्धा, समर्पण, कृतज्ञता और विनम्रता का प्रतीक मानते है। कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर या किसी विशेष संकल्प के तहत भी अपने केश अर्पित करते हैं। तिरुमला में केश दान की यह परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है।

आईएनएस त्रिकंद ने फिर दिखाई ताकत, समुद्री डाकुओं की साजिश की नाकाम

नई दिल्ली। अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के चंगुल से एक व्यापारी जहाज को सुरक्षित बचाने के बाद भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद एक बार फिर चर्चा में है। हालिया अभियान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत अब केवल अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रहा है। हाल ही में अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं ने व्यापारी जहाज एमवी गोल्डन आर्सेनल को निशाना बनाने की कोशिश की। संकट का संदेश मिलते ही क्षेत्र में तैनात आईएनएस त्रिकंद को तत्काल रवाना किया गया। युद्धपोत के पहुंचते ही भारतीय नौसेना की बोर्डिंग टीम ने जहाज की तलाशी ली और पूरे अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए चालक दल के सभी 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया।

पीओके में इमरान खान की पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया

कश्मीरियों के लिए मांगा न्याय

वेब वार्ता, इस्लामाबाद

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल जारी है। इस अशांत माहौल के बीच, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने 27 जुलाई को होने वाले पीओके विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का एक बड़ा और अप्रत्याशित फैसला लिया है। पार्टी का कहना है कि यह निर्णय किसी राजनीतिक लाभ या नुकसान के डर से नहीं लिया गया है, बल्कि मौजूदा परिस्थितियों और क्षेत्र में कश्मीरियों के साथ एकजुटता दिखाने और लोकतंत्र के सम्मान में उठाया गया है। पीटीआई, जो वर्तमान में पाकिस्तान की केंद्र सरकार में एक प्रमुख विपक्षी दल है, ने साफ किया है कि जब तक एक स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण राजनीतिक माहौल नहीं बन जाता, तब तक वह किसी भी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगी। इस कदम से न केवल चुनावों की वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं, बल्कि पीओके में पाकिस्तान की कठपुतली सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष को भी बल मिला है।

पीटीआई के प्रवक्ता द्वारा जारी बयान में प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पार्टी ने कहा कि पीओके इस वक्त गंभीर संकट से जूझ रहा है, जहां रावलकोट समेत कई अन्य हिस्सों में हजारों नागरिक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और अधिकारों के लिए धरने पर बैठे हैं। हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद, पीओके की कठपुतली सरकार ने 5 जून को आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) के तहत जेएएसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध 9 जून को होने वाले जेएएसी के एक प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले लगाया गया था, जिसमें 1947 के बाद जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान गए शरणार्थियों के लिए पीओके में आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग की जानी थी। यह मांग स्थानीय आबादी के बीच गहरे असंतोष को दशार्ती है, जो बाहरी लोगों के बजाय अपनी समस्याओं के लिए अपनी ही भूमि पर प्रतिनिधित्व चाहते हैं।

उज्जैन में मूसलाधार बारिश: मंदिर डूबे, जनजीवन प्रभावित

वेब वार्ता, भोपाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगातार हो रही वर्षा के कारण पवित्र शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे प्रसिद्ध रामघाट के आसपास स्थित कई छोटे-बड़े मंदिर पानी में डूब गए। घाट के कई हिस्सों तक नदी का पानी पहुंचने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है

राजधानी भोपाल में भी अनेक निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया, जिससे जाम की स्थिति बनी नाले उफान पर रहे जिससे अनेक घरों में जलभराव हुआ इससे लोगों को खासी परेशानी हुई इस तरह पहली बारिश ने ही शासन-प्रशासन के तमाम दावो की पोल खोलकर रख दी लगातार बारिश के चलते उज्जैन शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और कई स्थानों पर लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा उससे सटे उत्तर ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले पांच से छह दिनों तक मध्य भारत में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है।

अभी कम नहीं होंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें, कंपनियों के घाटे ने उम्मीद पर फेरा पानी

पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर 2.19 लाख करोड़ घाटे से सरकार चिंतित

वेब वार्ता, नई दिल्ली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को जानकारी दी कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तीव्र बढ़ोतरी के कारण सरकारी तेल विपणन कंपनियों को 30 जून तक पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बिक्री पर कुल 2.19 लाख करोड़ की अंडर-रिकवरी हुई है। सरकार ने साफ किया है कि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक निचले स्तर पर बनी रहती हैं, तभी ईंधन की खुदरा कीमतों में कटौती पर विचार किया जाएगा।

पूरी की यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है जब आम जनता पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी की उम्मीद कर रही है, लेकिन कंपनियों को हो रहे इस बड़े घाटे ने तत्काल राहत की संभावनाओं पर पानी फेर दिया है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में अकेले पेट्रोल पर 19,905 करोड़, डीजल पर 1.44 लाख करोड़ और एलपीजी पर 24,148 करोड़ की अंडर-रिकवरी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, पिछली तिमाहियों की एलपीजी अंडर-रिकवरी 30,720 करोड़ रही। अंडर-रिकवरी का सीधा अर्थ है कि जब तेल कंपनियां किसी उत्पाद को उसकी लागत से कम कीमत पर बेचती हैं, तो जो अंतर आता है, उसे अंडर-रिकवरी कहते हैं। यह किसी कंपनी के समग्र वित्तीय प्रदर्शन में होने वाले शुद्ध नुकसान से अलग होती है, जिसमें सभी उत्पादों से होने वाला लाभ-हानि शामिल होता है।

मंत्री ने इस विरोधाभास को स्पष्ट किया कि जहां एक ओर कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें अप्रैल में 120 डॉलर प्रति बैरल से घटकर अब करीब 72 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं, वहीं दूसरी ओर घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों में कमी क्यों नहीं आ रही है। उन्होंने बताया कि तेल कंपनियों को अभी भी एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर घाटा हो रहा है।

...सीधा असर देश के ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ता है

भारतीय तेल कंपनियों ने चार साल के अंतराल के बाद, 15 मई, 2026 को पेट्रोल की कीमत में 7.38 प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7.52 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी ताकि बढ़ते घाटे की भरपाई की जा सके। पुरी ने भारत की मजबूत रिफाइनिंग क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश ने ईंधन की आपूर्ति सुचारु रूप से बनाए रखी। हालांकि, उन्होंने भविष्य में संभावित आपूर्ति बाधाओं से बेहतर ढंग से निपटने के लिए देश की तेल भंडारण क्षमता को बढ़ाने की जरुरत पर जोर दिया। बता दें वर्तमान में भारत के पास करीब 76 से 80 दिनों का तेल भंडार है, जिसे और बढ़ाने की जरूरत है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए वैश्विक बाजार पर अत्यधिक निर्भर है, जहां करीब 90 फीसदी कच्चा तेल, 50 फीसदी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और 60 फीसदी एलपीजी आयात किया जाता है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों का सीधा असर देश के ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ता है।

संपादकीय

ये पाकिस्तान के पैरोकार

भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों करे? राजनयिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पेशेवर रिश्ते क्यों बहाल करे? एक आतंकिस्तान देश को सबक सिखाना चाहिए अथवा संवाद के जरिए मुहब्बत का इजहार करना चाहिए? जो 117 चेहरे आज पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं, क्या वे भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है? क्या वे पहलगाम का नरसंहार भूल गए? क्या पुलवामा में 40 शहीदों की कुबार्नी भूल गए? क्या उरी से लेकर 26/11 मुंबई आतंकी हमले तक पाकपरस्त शैतानों और हत्यारों की साजिशें भी भूल गए? क्या इन पैरोकारों ने आतंकवाद में अपने किसी परिजन को खोया है? यह पीड़ा, हत्या, दर्द, खालीपन, सूने आंगन, उजड़े सिंदूर को कैसे और कौन भूल सकता है? आखिर भारत की मजबूरी क्या है, जो वह पाकिस्तान की आतंकी, हत्यारी हुकूमत के साथ बातचीत करे? इस भूखे, नंगे, कर्जदार देश के पल्ले क्या है, जो वह भारत को मुहैया करा सकता है? और फिर क्या गारंटी है कि संवाद और संबंधों की बहाली के बाद सरहदों पर तनाव ठहर जाएगा? सीमापार से आतंकी भेजे नहीं जाएंगे? वैश्विक मंचों पर, कश्मीर की आड़ में, भारत-विरोधी दुष्प्रचार थम जाएंगे? सांप की फितरत बदली है कभी? जिन 117 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और कथित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खुला पत्र लिख कर भारत-पाक संवाद और बेहतर, कारगर संबंधों की गुहार की है, उनमें जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के अलावा, पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर और सैफुद्दीन सोज भी शामिल हैं। मणिशंकर ने सलमान खुर्शीद के साथ पाकिस्तान जाकर गुहार की थी कि मोदी सरकार हटाने में मदद करें। यह नवंबर, 2015 का वाकया है। दोनों कथित कांग्रेस नेताओं का कहना था कि मोदी को हटाए बिना भारत-पाक संबंध बेहतर नहीं हो सकते। अब पैरोकारों की सूची में शामिल हैं, तो वह बिल्कुल बेमानी है।

खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख रहे एएस दुल्लत भी सूची में हैं, जो पाकिस्तान की रूह तक से वाकिफ हैं और कई आतंकी हमलों के साक्षी रहे हैं। ओपी शाह, मनोज झा, जवाहर सरकार आदि कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, यह हम नहीं जानते, लेकिन सूची में जो 61 नाम भारतीयों के हैं, वे यकीनन प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर विरोधी हैं और पाकपरस्त चेहरे हैं। आज उन्हें कौन पूछता है? क्या प्रासंगिकता है इनकी? क्या इनमें से किसी ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि आतंकी सांपों को पालना बंद करें? उनके अड्डे खत्म किए जाएं। हुकूमत और फौज आतंकियों की आर्थिक मदद करना और उन्हें जेहादी समर्थन देना भी बंद करें। दरअसल आतंकवाद का जिक्र जब भी होता है, तो ये पैरोकार हकलाने लगते हैं या गाली की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अरे, पाकिस्तान के मंत्री धमकी दे रहे हैं कि हमने 130 परमाणु हथियार भारत के लिए रखे हैं। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आजकल एटमी युद्ध की धमकी दे रहे हैं। एक नापाक मंत्री ने यहां तक कह दिया कि पानी को हाथ लगाया, तो हाथ तोड़ देंगे। पाकिस्तान के कथित उपप्रधानमंत्री इशाक डार सिंधु नदी का पानी रोकना युद्ध की कार्रवाई मानते हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर के हमले भूल गया है पाकिस्तान, जिनमें उसके 11 एयरबेस को मिट्टी-मलबा कर दिया गया था? बहरहाल ऐसे आतंकी, धमकीबाज मंत्रियों की हुकूमत से भारत बात करेगा! क्यों करेगा? क्या ये 117 रिटायर्ड चेहरे भूल गए हैं कि पाकिस्तान में बसे और सक्रिय आतंकियों ने हमारे 40,000 से अधिक बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं? मठ-मंदिर ध्वस्त किए हैं? औरतों की आबरू, अस्मत लूटी है? पाकिस्तान में कौन लोग हैं, जो आपसी रिश्ते बेहतर चाहते हैं? अवाम को तो आटा, दाल, चावल, चीनी, फल-सब्जी भी मयस्सर नहीं है। क्या ऐसे अवाम को भयानक, कुरूप यथार्थों की पूरी जानकारी है? पाकिस्तान पहले बलूचिस्तान, खैबर, कथित आजाद कश्मीर में तो हालात शांत करे। वहां नापाक फौज अवाम को सरेआम गोलियों से भून रही है। अवाम विद्रोह पर है और सडकों पर आंदोलित है। जिसका अपना घर विभाजित है, टुकड़े-टुकड़े है, उससे भारत क्या बात करेगा और उससे क्या हासिल होगा? पैरोकारों को एक-दूसरे के फॉर्म हाउस में पार्टी करनी है और बिरयानी का लुत्फ उठाना है, तो वे स्वतंत्र हैं। भारत किसी आतंकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा।

कब होगा नगद ईनाम बांट समारोह?

खेलों में अग्रणी राज्य हरियाणा व केरल अपने प्रशिक्षकों को भी समय समय पर नगद ईनाम अपने विजेता खिलाड़ियों के साथ देता है। हिमाचल पीछे क्यों रह रहा है। आज का अभिभावक खेलों में भी अपने बच्चों का कैरियर देख रहा है क्योंकि खेल आज अपने आप में एक प्रोफैशन है। मानव द्वारा विज्ञान में बहुत प्रगति कर प्रौद्योगिकी व चिकित्सा के क्षेत्र में नए-नए सफल शोध कर जीवनशैली को काफी आसान व सुविधाजनक बना लिया है, मगर शिक्षण व प्रशिक्षण में शिक्षक व प्रशिक्षक की भूमिका का महत्व आज भी वही है, जैसा हजारों साल पहले था। महाभारत में कृष्ण सारथी नहीं होते तो क्या अर्जुन भीष्म, कर्ण व अन्य अजेय महारथियों को हरा पाता? हिमाचल में प्रशिक्षण की हर सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि बेहतर परिणाम आएं।

हिमाचल सरकार को भी चुने हुए चौथा बर्ष भी आधा खत्म हो रहा है, मगर ये सरकार भी राज्य के वरिष्ठ व कनिष्ठ राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए ईनाम बांट समारोह आयोजित नहीं कर पाई है। हां, यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री ने नई खेल नीति बनाने की घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए बजट में ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता की नगद ईनामी राशि को तीन करोड़ रुपए से पांच करोड़ रुपए, रजत पदक के दो करोड़ रुपए को तीन करोड़ रुपए व कांस्य पदक विजेता के एक करोड़ रुपए को दो करोड़ रुपए तक जरूर बढ़ाया है। एशियन व राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं के नगद ईनाम में भारी बढ़ोतरी कर एशियाड के स्वर्ण पदक विजेता के पचास लाख रुपए को चार करोड़ रुपए, रजत के बीस लाख रुपए को अढाई करोड़ रुपए व कांस्य पदक विजेता के बीस लाख रुपए को डेढ़ करोड़ तथा राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को तीन करोड़, रजत के लिए दो करोड़ रुपए व कांस्य पदक विजेता को एक करोड़ रुपए तक बढ़ा कर हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। ओलंपिक व अन्य गेम्स के पदक विजेताओं को नगद ईनाम भी दे दिया है, मगर राष्ट्रीय पदक विजेताओं को कब ईनाम मिलेगा, यह तय नहीं है। पिछले एक दशक में हिमाचल के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में दर्जनों पदक जीते हैं, मगर उनका सरकार ने अभी तक अभिनंदन तक नहीं किया है।

खेलों से सरकारों की इतनी बेरुखी ठीक नहीं है। अभी भी समय है कि ईनाम बांट समारोह सरकार जल्द से जल्द करवाए। डेढ़ दशक पूर्व जब हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अंतरराष्ट्रीय खेलों के पदाधिकारियों की ईनामी राशि को लाखों से करोड़ों में किया था, तो उसके बाद हरियाणा में खिलाड़ियों व उनके अभिभावकों ने अपने बच्चों का कैरियर खेलों में तलाशना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में ड्रिल व खेलों के लिए एक पीरियड जो वर्षों पहले पढ़ाई के नाम पर खत्म कर दिया था, अब फिर से शुरू करने का क्रांतिकारी कदम उठा कर सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों की फिटनेस को ध्यान में रखने को तो जरूर कहा है, मगर खेलों के प्रशिक्षण व प्रतियोगिताओं के लिए समय सीमित कर दिया है जो कथनी व करनी में बहुत फर्क दिखा रहा है। प्रतियोगिता व प्रशिक्षण शिविरों के समय खिलाड़ियों को खाने में बहुत दिक्कत रहती है। सरकार द्वारा खुराक भत्ता बढ़ाना हिमाचल प्रदेश की खेलों व खिलाड़ियों के लिए अच्छा संकेत है, मगर साथ ही साथ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण व प्रतियोगिताओं के लिए उचित समय देकर खेलों के साथ न्याय करे। ओलंपिक 2036 भारत में आयोजित करवाने की बात हो रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस स्तर पर भारत का प्रदर्शन भी उत्कृष्ट हो। इसलिए भारत में अच्छे प्रशिक्षकों को सही सुविधा व प्रबंधन देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि खिलाड़ी से उच्च परिणाम केवल प्रशिक्षक ही दिलाता है मगर कांग्रेस सरकार की इस ईनाम बढ़ोत्तरी में प्रशिक्षक को मिलने वाले नगद ईनाम पर चुप्पी क्यों है।

खेलों में अग्रणी राज्य हरियाणा व केरल अपने प्रशिक्षकों को भी समय समय पर नगद ईनाम अपने विजेता खिलाड़ियों के साथ देता है। हिमाचल पीछे क्यों रह रहा है। आज का अभिभावक खेलों में भी अपने बच्चों का कैरियर देख रहा है क्योंकि खेल आज अपने आप में एक प्रोफैशन है। मानव द्वारा विज्ञान में बहुत प्रगति कर प्रौद्योगिकी व चिकित्सा के क्षेत्र में नए-नए सफल शोध कर जीवनशैली को काफी आसान व सुविधाजनक बना लिया है, मगर शिक्षण व प्रशिक्षण में शिक्षक व प्रशिक्षक की भूमिका का महत्व आज भी वही है, जैसा हजारों साल पहले था। महाभारत में कृष्ण सारथी नहीं होते तो क्या अर्जुन भीष्म, कर्ण व अन्य अजेय महारथियों को हरा पाता?

विश्व स्तर पर किसी खेल विशेष में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए क्षमतावान प्रशिक्षक का होना बेहद जरूरी होता है। आशा करते हैं कि सरकार उन्हें भी सम्मानजनक ईनामी राशि देगी। खेलों के क्षेत्र में हिमाचल को अभी कई कुछ करना बाकी है। हिमाचल के कई खिलाड़ी प्रशिक्षण सुविधा की कमी के कारण बाहर के राज्यों में चले जाते हैं और बाद में उसी राज्य से खेलते हैं। हिमाचल के लिए इसे प्रतिभा का पलायन माना जा सकता है। प्रदेश में ही प्रशिक्षण की हर सुविधा विकसित करनी होगी, ताकि हमारे खिलाड़ी हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकें। कुछ निजी प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रखी है। ऐसे प्रशिक्षकों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अगर युवाओं को अच्छा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, तो वे बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बहरहाल, प्रदेश सरकार को नगद पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन जल्द से जल्द करना चाहिए।

भूपिंद्र सिंह
अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रशिक्षक

घोटाला, घोटाला, घोटाला

हमारा देश घोटाला प्रधान है। घोटालों में हमारा मुकाबला नहीं है। ओलंपिक्स में यदि घोटाला प्रतियोगिता हो तो निःसंदेह हम हर हालत में स्वर्ण पदक प्राप्त करके रहें। एक घोटाले की जांच प्रारंभ भी नहीं हो पाती कि दूसरा खुल पड़ता है। मेरे एक मित्र हैं। घोटालों के अनुभव सिद्ध पुरुष हैं। तीन बार गबन-घोटाले के चक्कर में निलंबित हो चुके हैं। लेकिन हर बार न्यायालय उन्हें बेदाग साबित करके पुनः सेवा में बहाल कर देता है और वे फिर घोटाला प्रक्रिया में लिप्त हो जाते हैं।

एक दिन आए तो मैंने कहा, मित्रवर, घोटालों के कीर्तिमान तोड़े जा रहे हैं और आप हैं कि दम साधे पड़े हैं। शर्मा क्या बताऊं यार, घोटाला तो कर चुका, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। तो क्या मैं आशा करूं कि यह घोटाला नए आयाम छू लेगा? मैंने पूछा। वे बोले- कह नहीं सकता, मैं जहां काम करता हूं, वहां का कुल बजट ही जब लाखों में है तो करोड़ों का घपला कैसे हो सकता है? यह तो तुम जानो, लेकिन गुरु करो कुछ ऐसा कि एकदम ओरिजनल हो। मैं बोला। भाई जैसी भी सेवा बन पड़ रही है, कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर भी हम लोग इतने बड़े रिस्क ले रहे हैं। क्या तुम घपला कर सकते हैं?

उन्होंने पूछा। मैंने कहा- अजी मेरी क्या बिसात। मैं तो करते आप हो लेकिन डर मुझे लगता है। कई बार तो लगता है कि कहीं तुम्हारा दोस्त हूं, कोई आंच की चिंगारी मुझ पर न लग जाए। ऐसा बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूं भाई। कीर्तिमान मुझे कायम करने हैं और गिनीज बुक में नाम तुम दर्ज कराओ। वे बोले। मैंने कहा- तो क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए ही करते हो घोटाले? देखो कोई न कोई लक्ष्य तो सामने रखना ही पड़ता है। बिना आदर्श योजना के काम करना मैं उचित नहीं मानता। घोटाले का भी अपना शास्त्र है तथा वह यह तो नहीं कहता कि घोटालों का कोई औचित्य नहीं है। क्या खूब कही है आपने तो भाई। अब जरा यह भी तो बताओ जो तुम्हारे बड़े भाई अरेस्ट हो गए हैं शेयर घोटालों में, उनका भविष्य क्या है? उनका भविष्य उज्ज्वल है। घोटालों पर पर्दा डालने में हमारा सरकारी तंत्र प्रवीण है।

वह नहीं चाहता कि अरबों रुपए के घोटाले भी सामने आए, फिर आजकल तो बड़े-बड़े स्कैण्डल्स से जुड़ने का क्रेज भी है। मंत्रीगण वगैरह हर काण्ड में जुड़े मिलते हैं। सत्तारूढ़ लोगों की तो विशेषता ही यही है कि वे कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। मित्र महाशय ने कहा। मैं बोला- लेकिन सरकार इन आर्थिक अपराधियों को शह क्यों देती है? शह देकर मात देना शतरंज का खेल है। राजनीति शतरंज की चाल हो गई है, जिसमें हर मोहरा बड़ा सोच समझ कर रखना होता है। इससे होता यह है कि राजनीतिक दलों की पांचों अंगुलियां घी में तर रहती हैं और फिर अब तो चुनाव भी जल्दी-जल्दी कराने का फैशन सा हो गया है। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। उस समय चंदा मिलता ही घोटालों से है और चुनाव जीत लिया जाता है। उन्होंने कहा। मैंने कहा- लेकिन यह मूल्यहीनता है तथा सरासर दगा है। मूल्यहीनता, जाओ पहले बाजार भाव मालूम करके आओ, कुछ क्रय शक्ति हो तो हमें भी बताओ। इतनी देर से गाल बजा रहे हो। हमें देखो जेबें नोटों से भरी रहती हैं तथा इसकी मार से जमाने को झुकाए चले जाते हैं। इसलिए यही तो घोटाला महात्म्य है।

पूरन सरमा
स्वतंत्र लेखक

नैनो उर्वरक–छत्तीसगढ़ के खेती–किसानी में आई नई क्रांति

छत्तीसगढ़ को देश का धान का कटोरा कहा जाता है। यहां की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है और किसानों की समृद्धि राज्य के विकास से सीधे जुड़ी हुई है। बदलते समय के साथ खेती में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है, जिनमें नैनो उर्वरक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में उभरा है। कम लागत, अधिक प्रभाव और पर्यावरण संरक्षण जैसे गुणों के कारण नैनो उर्वरक आज किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा हैं।

नैनो उर्वरक अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं, जिन्हें पौधे तेजी से और अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं। इसके कारण पौधों को आवश्यक पोषक तत्व सही समय पर उपलब्ध हो जाते हैं और फसलों का विकास बेहतर तरीके से होता है। पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में इनकी मात्रा कम लगती है, जिससे किसानों का खर्च घटता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। छत्तीसगढ़ में धान, मक्का, चना, अरहर तथा सब्जी फसलों में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। प्रदेश में कई किसानों ने अनुभव किया है कि नैनो उर्वरकों के प्रयोग से फसल की पैदावार बेहतर होती है, पौधे अधिक हरे-भरे रहते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

नैनो उर्वरकों का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इनके उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव कम पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से जहां भूमि की गुणवत्ता प्रभावित होती है, वहीं नैनो उर्वरक संतुलित पोषण प्रदान कर मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करते हैं। साथ ही जल स्रोतों में रासायनिक तत्वों के बहाव को भी कम करते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।

परिवहन और भंडारण की दृष्टि से भी नैनो उर्वरक काफी सुविधाजनक हैं। पारंपरिक उर्वरकों की भारी बोरियों की जगह छोटी बोतलों में उपलब्ध नैनो उर्वरक किसानों के लिए आसानी से ले जाने और उपयोग करने योग्य होते हैं। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है।

छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया जैसे उन्नत उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देकर खेती को अधिक उत्पादक, किफायती और टिकाऊ बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक और नवाचार आधारित खेती ही भविष्य की कृषि का आधार है। नैनो उर्वरकों का उपयोग न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि व्यवस्था को भी बढ़ावा देगा।

छत्तीसगढ़ सरकार तथा कृषि विभाग किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए लगातार प्रेरित कर रही हैं। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने भी राज्य के किसानों से अपील की है कि वे वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और नवीन तकनीकों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी बनाएं। उन्होंने किसानों को नैनो उर्वरकों के उपयोग के प्रति जागरूक होने तथा कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार इनका प्रयोग करने का आग्रह किया है, ताकि उत्पादन बढ़े, लागत घटे और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

वर्तमान में कृषि क्षेत्र में बढ़ती लागत और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बीच नैनो उर्वरक किसानों के लिए एक प्रभावी विकल्प बनकर सामने आए हैं। यह तकनीक कम खर्च में बेहतर उत्पादन, स्वस्थ मिट्टी और सुरक्षित पर्यावरण का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि छत्तीसगढ़ के किसान वैज्ञानिक सलाह और संतुलित उपयोग के साथ नैनो उर्वरकों को अपनाते हैं, तो आने वाले समय में यह राज्य की कृषि उन्नति और किसानों की आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बन सकता है। निस्संदेह, नैनो उर्वरक छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए आधुनिक खेती का नया वरदान साबित हो सकता है।

तेजबहादुर सिंह भुवाल
लेखक सहा. जनसंपर्क अधिकारी हैं

आलेख

दुःख का कारण : अंतहीन कामनाएँ – इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्चे सुख, शांति और संतोष का मार्ग

मानव जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। मन में उठने वाली इच्छाएँ, आकांक्षाएँ और कामनाएँ ही व्यक्ति के जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। यदि मन शुभ विचारों, संयम और संतोष से प्रेरित हो तो जीवन सुख, शांति और संतुलन की ओर अग्रसर होता है, किंतु यदि मन अनंत इच्छाओं और अप्रशस्त कामनाओं का दास बन जाए तो वही जीवन तनाव, अशांति और दुःख का कारण बन जाता है। यही कारण है कि भारतीय अध्यात्म, विशेषकर भगवान महावीर की शिक्षाओं में कामनाओं पर नियंत्रण को सुखी जीवन का मूल मंत्र बताया गया है।

मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है। उसमें हर क्षण नए विचार जन्म लेते हैं। कभी सेवा का भाव जागता है तो कभी स्वार्थ का, कभी त्याग की प्रेरणा मिलती है तो कभी संग्रह की इच्छा प्रबल हो जाती है। प्रायः लोग अपनी अशांति का दोष मन पर डालते हैं और कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, वह किसी की नहीं सुनता। किंतु यह सत्य नहीं है। मन हमारा अपना है और उस पर अधिकार भी हमारा ही होना चाहिए। यदि अभ्यास, विवेक, वैराग्य और आत्मजागृति के माध्यम से मन को साधा जाए तो वह जीवन का सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। इसलिए आवश्यक है कि जैसे ही मन में अनावश्यक इच्छाएँ जन्म लें, उसी क्षण उन्हें रोकने का प्रयास किया जाए।

भगवान महावीर ने कहा है कि मनुष्य की कामनाएँ आकाश की तरह अनंत होती हैं। जिस प्रकार आकाश का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यही क्रम जीवनभर चलता रहता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई इच्छा न हो। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना स्वाभाविक है, किंतु जब आवश्यकताएँ लालसा का रूप धारण कर लेती हैं, तब वही इच्छाएँ मनुष्य को दुःख के गर्त में धकेल देती हैं। अनावश्यक कामनाएँ मन को तनाव, असंतोष और बेचैनी से भर देती हैं तथा व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता।

कामनाएँ दो प्रकार की होती हैं–प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त कामनाएँ वे हैं जो आत्मकल्याण और लोकमंगल का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जैसे धर्म, गुरु और देव की सेवा करना, दुःखी व्यक्ति की सहायता करना, संतों का सान्निध्य प्राप्त करना, स्वाध्याय करना, तप करना तथा प्रभु स्मरण में मन लगाना। ऐसी इच्छाएँ व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती हैं और उसके भीतर करुणा, विनम्रता तथा आत्मशुद्धि का विकास करती हैं। इसके विपरीत अप्रशस्त कामनाएँ केवल भौतिक सुख-सुविधाओं, संग्रह, अहंकार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं। इन्हीं के कारण व्यक्ति दूसरों से तुलना करता है और 'और अधिक' पाने की लालसा में अपना वर्तमान सुख खो देता है।

आज का समाज इसी 'और अधिक' की मानसिकता से ग्रस्त दिखाई देता है। यदि किसी के पास एक घर है तो वह दूसरा चाहता है, दूसरा मिल जाए तो तीसरे की इच्छा जन्म लेती है। व्यापार अच्छा चल रहा हो तो और अधिक विस्तार की लालसा बढ़ जाती है। धन, पद और प्रतिष्ठा की यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। व्यक्ति सोचता है कि अगली उपलब्धि मिलने पर वह सुखी हो जाएगा, किंतु वास्तविकता यह है कि प्रत्येक नई उपलब्धि के साथ नई इच्छाएँ भी जन्म ले लेती हैं। परिणामस्वरूप जीवन में संतोष का स्थान असंतोष ले लेता है और मनुष्य निरंतर चिंता, तनाव और अशांति में जीने लगता है।

इस संदर्भ में एक उद्योगपति के पुत्र का प्रसंग अत्यंत विचारणीय है। उसके परिवार के पास धन, वैभव और सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वे नए-नए उद्योग स्थापित करने और अधिक धन अर्जित करने की चिंता में लगे रहते थे। पुत्र ने स्वयं प्रश्न किया कि जब सब कुछ उपलब्ध है तो फिर यह अंतहीन दौड़ किसलिए? वास्तव में यही प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए। आखिर वह किस सीमा तक संग्रह करेगा, जबकि एक दिन उसे सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है? यदि यह सत्य मनुष्य के हृदय में उतर जाए तो उसकी अनेक अनावश्यक इच्छाएँ स्वतः समाप्त हो सकती हैं।

विश्वविजेता सिकंदर का जीवन भी यही शिक्षा देता है। उसने संपूर्ण विश्व को जीतने का सपना देखा, अनेक युद्ध लड़े और अपार धन-संपत्ति अर्जित की, किंतु मृत्यु के समय उसे अनुभव हुआ कि वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। इसलिए उसने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि उसके दोनों हाथ जनाजे के बाहर रहें, ताकि संसार देख सके कि विश्वविजेता भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। यह प्रसंग मनुष्य को स्मरण कराता है कि धन, वैभव और सत्ता स्थायी नहीं हैं। यदि वे स्थायी नहीं हैं तो उनके पीछे अपना संपूर्ण जीवन नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती।

भगवान महावीर ने स्पष्ट कहा कि अनावश्यक कामनाओं पर नियंत्रण ही दुःख से मुक्ति का उपाय है। उन्होंने आहार, भय, मैथुन और परिग्रह जैसी चार मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए बताया कि इन्हें जितना बढ़ाया जाएगा, वे उतनी ही बढ़ती जाएँगी और जितना संयमित किया जाएगा, उतनी ही नियंत्रित होती जाएँगी। इसलिए आत्मसंयम का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय प्राप्त करने में है। जिसने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया, वही वास्तविक अर्थों में समृद्ध और सुखी है।

शांति कभी जंगलों, पर्वतों या बाहरी साधनों में नहीं मिलती। शांति मन की अवस्था है, जो संतोष, संयम और आत्मनियंत्रण से उत्पन्न होती है। वैभव के दीपक से शांति का प्रकाश नहीं फैलता, बल्कि अंतर्मन की निर्मलता से वह प्रकाशित होती है। इच्छाओं की आग में जलने वाला व्यक्ति न तो चैन से भोजन कर सकता है, न आराम से सो सकता है और न ही अपने परिवार तथा समाज के साथ सहज संबंध बना सकता है। उसकी सारी ऊर्जा केवल इच्छाओं की पूर्ति में व्यय होती रहती है। इसके विपरीत संतोषी व्यक्ति सीमित साधनों में भी आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करता है।

आचार्य उमास्वाति का सूत्र ₹इच्छा निरोधस्तपः₹ इस सत्य को अत्यंत सरल शब्दों में व्यक्त करता है। अर्थात इच्छाओं का निरोध ही सबसे बड़ा तप है। जिसने अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली, उसे किसी अन्य कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं रहती। यद्यपि इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना सरल नहीं है, किंतु निरंतर अभ्यास, आत्मचिंतन, बारह भावनाओं के मनन, स्वाध्याय और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से यह संभव हो सकता है। धीरे-धीरे मन की चंचलता शांत होती है और व्यक्ति के भीतर संतोष, करुणा तथा आत्मानंद का प्रकाश फैलने लगता है।

आज के भौतिकवादी युग में भगवान महावीर का यह संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन ने सुविधाएँ तो बढ़ा दी हैं, परंतु संतोष कम कर दिया है। ऐसे समय में यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच का अंतर समझ ले, प्रशस्त और अप्रशस्त कामनाओं का विवेकपूर्वक चयन करे तथा धर्म, अध्यात्म और परमार्थ को जीवन का आधार बनाए, तो उसका जीवन वास्तव में सुखमय बन सकता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि दुःख का मूल कारण बाहरी अभाव नहीं, बल्कि अंतहीन कामनाएँ हैं। इच्छाओं का संयम, संतोष का विकास और आत्मनियंत्रण ही सच्चे सुख, शांति और जीवन की सार्थकता का वास्तविक मार्ग है।

कांतिलाल मांडोत
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार-स्तम्भकार है)

संक्षिप्त वार्ता

मोहन सिंह बिष्ट ने किया शिव विहार में नई पेयजल लाइन का उद्घाटन

नई दिल्ली, 03 जुलाई (वेब वार्ता)। मुस्तफाबाद विधानसभा के शिव विहार क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल संकट की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्थानीय विधायक व दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने नई पेयजल पाइपलाइन बिछाने के कार्य का उद्घाटन किया। क्षेत्र में लंबे समय से दूषित और गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें मिल रही थीं। स्थानीय लोग लगातार विधायक कार्यालय और संबंधित विभाग के समक्ष समस्या उठा रहे थे।

डीटीयू में लीडरशिप प्रोग्राम इन सीएसआर कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी

नई दिल्ली, 03 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) में लीडरशिप प्रोग्राम इन सीएसआर, ईएसजी एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस कोर्स में आवेदन के लिए पंजीकरण करने का अंतिम दिन रविवार है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह छह महीने का कोर्स है। इसमें चयनित उम्मीदवार को तीन दिन कैंपस व बाकी दिन ऑनलाइन कोर्स कराया जाएगा।

कक्षाएं 26 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। इसमें सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों के अनुरूप रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता विकसित करना व पेशेवरों को बिजनेस मॉडल और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को लेकर सिखाया जाएगा। डीटीयू के अधिकारियों ने बताया कि इसमें कंसल्टेंट, पॉलिसी प्रोफेशनल और सस्टेनेबिलिटी अधिकारी समेत मध्य से वरिष्ठ स्तर के पेशेवर शामिल हो सकते हैं।

इस प्रोग्राम की कक्षाएं लाइव लेक्चर के जरिए होंगी। इसमें केस स्टडी, इंटरैक्टिव सेशन, क्विज, मिड-टर्म और एंड-टर्म परीक्षाएं, प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप बेस्ड प्रेजेंटेशन सहित कई तरह गतिविधियां शामिल हैं। ये सब डीटीयू फैकल्टी कराएगी। इस कोर्स में आवेदन करने वाले उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए डीटीयू की अधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं।

रोहतक रोड के मुंडका चौक पर 10 दिन यातायात प्रभावित, यूईआर-2 का उपयोग करें

नई दिल्ली, 03 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी दिल्ली में मुंडका चौक के पास पीडब्ल्यूडी द्वारा ड्रेनेज निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके यहां पर अगले 10 दिन तक यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को पीरागढ़ी से रोहतक रोड होते हुए रानी खेड़ा गांव जाने वाले यात्रियों को मुंडका चौक के प्रभावित हिस्से से बचने और वैकल्पिक मार्ग के रूप में यूईआर-2 को अपनाने की सलाह दी गई है।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, मुंडका या रोहतक रोड से रानी खेड़ा गांव की दिशा में जाने वाले वाहन चालक यूईआर-2 होते हुए रानी खेड़ा और आसपास के इलाकों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वे रोहतक रोड पर आगे बढ़कर श्मशान घाट रोड से दाएं मुड़कर भी रानी खेड़ा जा सकते हैं। वहीं, रानी खेड़ा गांव से मुंडका व रोहतक रोड की ओर आने वाले वाहन यूईआर-2 के रास्ते रोहतक रोड, मुंडका और इनके आसपास के इलाकों तक जा सकते हैं।

निजी संस्थान प्रबंधन कोटे से दे सकेंगे दाखिला : कोर्ट

नई दिल्ली, 03 जुलाई (वेब वार्ता)। हाईकोर्ट ने दिल्ली प्रोफेशनल कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस नियमों की वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान 10 फीसदी प्रबंधन कोटा सीटों पर प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) पास उम्मीदवारों में से अपनी अलग मेरिट सूची तैयार कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि यह नियम दिल्ली प्रोफेशनल कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस अधिनियम 2007 की योजना के अनुरूप है। उसके किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। यह फैसला जस्टिस फॉर ऑल की तरफ अधिवक्ता खगेश बी झा व अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया है। इस याचिका में अधिनियम की धारा 8(2)(ए)(वी) व शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दाखिला ब्रोशर को चुनौती दी गई थी।

मानसून में जलभराव वाले 77 स्थलों पर सीसीटीवी से होगी निगरानी

पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से जलभराव वाली जगहों पर निगरानी रखी जाएगी

राजधानी में मानसून का आगमन जल्द होने वाला है। राजधानी में मानसून के समय जलभराव न हो, इसे लेकर पीडब्ल्यूडी द्वारा व्यापक तैयारी की गई है।

नई दिल्ली, 03 जुलाई (वेब वार्ता)

इस वर्ष सीसीटीवी के जरिये उन 77 जगहों पर निगरानी रखी जाएगी जहां जलभराव की ज्यादा शिकायतें वर्ष 2025 में रही थी। इसके लिए सभी 77 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में 12वीं मंजिल पर कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां कर्मचारी 24 घंटे निगरानी के लिए तैनात रहेंगे। 1908 नंबर पर कॉल कर लोग यहां संपर्क कर सकेंगे।

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष जलभराव से निपटने के लिए 200 से ज्यादा मरम्मत वैन लगाई गई हैं जो जलभराव की समस्या का पता लगते ही मौके पर जाकर समाधान करेंगी। प्रत्येक वैन में पांच कर्मचारी होंगे जो उस क्षेत्र के नालों की जानकारी रखते होंगे। पीडब्ल्यूडी द्वारा निचली जगहों पर स्थायी पंप लगाए गए हैं ताकि वहां से पानी निकाला जा सके। वर्ष 2025 में जहां 157 स्थायी पंप स्टेशन में कुल 735 पंप काम कर रहे थे तो वहीं इस वर्ष 167 जगहों पर कुल 754 पंप लगाए गए हैं।

दिल्ली में 20 मीटर से ज्यादा चौड़ी लगभग 1400 किलोमीटर एवं 2123 किलोमीटर नाले पीडब्ल्यूडी के हैं। इन जगहों पर जलभराव रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी ने ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर करने से लेकर छोटे-बड़े नालों की सफाई का कार्य कर लिया गया है। 2123 किलोमीटर लंबे नालों में से 1955 किलोमीटर की सफाई का कार्य अभी तक पूरा किया जा चुका है। नाले से निकलने वाली गाद को 24 घंटे के भीतर हटाया जा रहा है ताकि वह दोबारा नाले में न जाए। उन्होंने पहले से तैयार नाले (प्री-कास्ट ड्रेन) के 89 टेंडर जारी किए हैं जिसमें से 31 पर काम शुरू हो गया है। वहीं अन्य 58 को लेकर काम चल रहा है।

जल-जमाव वाले स्थानों का अध्ययन

बारिश के दौरान जल-जमाव वाले ऐसे स्थानों का अध्ययन किया गया है, जहां आधे घंटे से ज्यादा समय तक पानी जमा रहता है और ट्रैफि क बाधित होता है। 2025 के बरसात के मौसम में जल-जमाव की आशंका वाली 77 जगहों की पहचान हुई थी। इन जगहों पर स्थायी समाधान के लिए, सभी 77 जगहों को कवर करते हुए 50 टेंडर जारी किए गए। इनमें से 4 जगहों पर काम पूरा हो चुका है, 25 टेंडर के तहत 42 जगहों पर काम चल रहा है जबकि 21 टेंडर के तहत 31 जगहों के लिए टेंडर देने की प्रक्रिया चल रही है।

जलभराव रोकने के लिए योजनाबद्ध कार्य

दिल्ली में जलभराव न हो, इसके लिए बीते कई महीनों से पीडब्ल्यूडी ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। दिल्ली सरकार ने नालों की सफाई कर जहां पानी के बहाव को लेकर बेहतर व्यवस्था की है तो वहीं जलभराव वाली संभावित जगहों की 24 घंटे निगरानी भी कर रही है। पीडब्ल्यूडी की वैन तुरंत ऐसी जगहों पर पहुंचकर पानी का बहाव ठीक करेगी ताकि लोगों को परेशानी न हो।

प्रवेश साहिब सिंह
पीडब्ल्यूडी मंत्री, दिल्ली सरकार

दिल्ली में शुरू होगी स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली परियोजना: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 03 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में वायु प्रदूषण की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार ह्यस्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्लीह्न परियोजना शुरू करने जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि यह पर्यावरण विभाग की एक महत्वाकांक्षी सात वर्षीय परियोजना है, जिसे विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय संस्थाओं के सहयोग से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिल्ली की वायु प्रदूषण जोखिम न्यूनीकरण योजना को तेजी से लागू करना, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान देना है।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने और सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 10 जुलाई को एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों की भूमिकाएं तय की जाएंगी और कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन की रूपरेखा पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में लागू की जाएगी। इसकी कुल अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपये है, जिसमें 65 प्रतिशत

वित्तीय सहायता विश्व बैंक उपलब्ध कराएगा, जबकि 35 प्रतिशत राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत परिवहन, सड़क की धूल, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (सीएंडडी) अपशिष्ट, ठोस कचरा प्रबंधन, उद्योग, हरित क्षेत्र और जल प्रदूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर काम किया जाएगा। यह केवल प्रदूषण नियंत्रण की योजना नहीं है, बल्कि दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और अधिक टिकाऊ शहरी पर्यावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक दीर्घकालिक निवेश है। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को दो प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है। पहला स्तंभ दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। इसके तहत परियोजना के प्रभावी संचालन के लिए एक समर्पित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) बनाई जाएगी। आधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी, डेटा एनालिटिक्स और एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा, इंडो-गंगा के मैदानी राज्यों के साथ मिलकर प्रदूषण नियंत्रण पर काम होगा तथा वैज्ञानिक योजना, जनजागरूकता, प्रशिक्षण और नई तकनीकों व नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा स्तंभ प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। इसके तहत पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर बनाया जाएगा तथा वाहनों से होने वाले प्रदूषण की निगरानी के लिए अत्याधुनिक प्रदूषण जांच (पीयूसी) प्रणाली विकसित की जाएगी।

12 गांव और 92 कॉलोनियों को ओ-जोन से बाहर करने की मांग उठाई

नई दिल्ली, 03 जुलाई (वेब वार्ता)

डीडीए की सलाहकार परिषद की पहली बैठक में दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने 12 प्राचीन गांव और 92 अनधिकृत कॉलोनियों को ओ-जोन से बाहर करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने 69 एफ्लुएंट कॉलोनियों को भी नियमित की गई 1511 कॉलोनियों की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया। बिधूड़ी ने बताया कि उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और डीडीए के उपाध्यक्ष डॉ. एन. सरवन कुमार ने इन मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सांसद सुधांशु त्रिवेदी सहित केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बिधूड़ी ने लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी को शीघ्र लागू करने के साथ ही मास्टर प्लान को जल्द नोटिफाई करने की मांग की, ताकि दिल्ली का नियोजित विकास हो सके। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की जमीन का उपयोग केवल गांव के निवासियों को नागरिक सुविधाएं देने के लिए किया जाना चाहिए। लालडोरा से बाहर की एक्सटेंडेड आबादी को भी 1511 कॉलोनियों की सूची में शामिल किया जाए। बैठक में बिधूड़ी ने अपोलो अस्पताल का मुद्दा भी उठाया, जिसे मात्र एक रुपए में जमीन दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और अस्पताल के बीच हुए एमओयू का पालन नहीं हो रहा। इस एमओयू के तहत 33 प्रतिशत बेड गरीबों के लिए आरक्षित होने चाहिए और ओपीडी में आने वाले 40 प्रतिशत गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त होना चाहिए।

हर्ष फायरिंग में महिला की मौत: भाजपा विधायक की सजा पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 03 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत होने के मामले में दोषी ठहराए गए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर अपना फैसला शुक्रवार को चार जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सिंह की सजा को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग-दो (गैर-इरादतन हत्या) और हथियार लाइसेंस संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है। सिंह (56) बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक हैं।

अदालत ने इससे पहले अपने 97 पृष्ठ के आदेश में कहा था, समारोहों के दौरान हर्ष फायरिंग की घटनाएं एक अभिशाप हैं जिनसे हमारे देश में अक्सर लोगों की जान चली जाती है। अदालत ने कहा था, यह मामला भी इसी तरह की एक घटना का उदाहरण है, जिसमें बिहार के कई बार विधायक रह चुके आरोपी राजू कुमार सिंह द्वारा 31 दिसंबर 2018 और एक जनवरी 2019 की दरमियानी रात को नव वर्ष की पार्टी में कथित तौर पर लापरवाही से की गई हर्ष फायरिंग के कारण एक अतिथि की मौत हो गई। अन्य आरोपियों ने घटना से जुड़े सबूत कथित तौर पर मिटाए। अदालत ने उसके समक्ष पेश सबूतों का उल्लेख करते हुए कहा था कि यह साबित हो गया है कि कई गवाहों ने सिंह की पहचान की और उसी ने वह गोली चलाई थी, जिससे अर्चना गुप्ता की मौत हुई।

यात्री को बेहोश कर सामान चुरा रहा बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। पुरानी दिल्ली रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने जहरखुरान गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान फिरोज खान के रूप में हुई है। डीसीपी बी.भरत रेड्डी ने बताया कि रेलवे पुलिस और आरपीएफ के जवान मंगलवार तड़के प्लेटफार्म संख्या 14 पर गश्त कर रहे थे। वह यहां खड़ी ट्रेन के डिब्बे में चढ़े, तो एक यात्री सीट पर अचेत मिला।

भाजपा नेता तजिंदर बग्गा ने ई-रिक्शा की बैटरियों को बंद कर रहे बैट-बीएमएस ऐप को तत्काल बंद करने की मांग

नई दिल्ली, 03 जुलाई (वेब वार्ता)। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर बग्गा ने ई-रिक्शा एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को दूर से बंद करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल एप्लिकेशन बैट-बीएमएस ऐप को तत्काल बंद करने की मांग की है। इस लेकर उन्होंने शुक्रवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है।

भाजपा नेता तजिंदर बग्गा ने पत्र में कहा कि बैट-बीएमएस ऐप नामक मोबाइल एप्लिकेशन का दुरुपयोग कर कुछ लोग ब्लूटूथ के माध्यम से ई-रिक्शा एवं अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों को दूर से बंद कर रहे हैं। इस संबंध में सोशल मीडिया पर अनेक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इस प्रकार की हरकतों के कारण ई-रिक्शा चालक बीच रास्ते में फंस जाते हैं, उनका काम प्रभावित होता है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जो लोग दिनभर की कमाई पर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, उनके लिए यह अत्यंत गंभीर समस्या है।

तजिंदर बग्गा ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो अत्यंत हृदयविदारक हैं। इनमें ई-रिक्शा चालक बीच सड़क पर फंसे हुए, मदद के लिए भटकते हुए तथा कई मामलों में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी दैनिक आय पर निर्भर इन मेहनतकश लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार न केवल अमानवीय है, बल्कि उनके सम्मान और आजीविका पर भी सीधा आघात है। जिसे कुछ लोग प्रैंक के नाम पर प्रचारित कर रहे हैं, वह वास्तव में गरीब परिवारों की रोजी-रोटी से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि चलते हुए वाहन को अचानक बंद कर देना बेहद खतरनाक है, इससे सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यह वास्तव में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। तजिंदर बग्गा ने बैट-बीएमएस ऐप को तत्काल बंद करने तथा गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर एवं अन्य प्लेटफॉर्म्स से हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

विश्व बैंक के सहयोग से प्रदूषण को कम करेगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली, 03 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी में वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली सरकार स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली परियोजना शुरू करने जा रही है।

यह पर्यावरण विभाग की एक महत्वाकांक्षी सात वर्षीय परियोजना है, जिसे विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय संस्थाओं के सहयोग से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में लागू होगी। इसकी कुल अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपये है, जिसमें 65 प्रतिशत वित्तीय सहायता विश्व बैंक उपलब्ध कराएगा, जबकि 35 प्रतिशत राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना की तैयारियों को अंतिम रूप देने और सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 10 जुलाई को एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों की भूमिकाएं तय की जाएंगी। इस परियोजना के तहत परिवहन, सड़क की धूल, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट, ठोस कचरा प्रबंधन, उद्योग, हरित क्षेत्र और जल प्रदूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर काम किया जाएगा। यह केवल प्रदूषण नियंत्रण की योजना नहीं है, बल्कि दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और अधिक टिकाऊ शहरी पर्यावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक दीर्घकालिक निवेश है।

मोदी सरकार लोगों पर जबरदस्ती थोप रही 20 प्रतिशत इथेनॉल मिला पेट्रोल : केजरीवाल

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों पर जबरदस्ती 20 प्रतिशत इथेनॉल मिला पेट्रोल थोपने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि मोदी सरकार के लिए पूरा देश प्रयोगशाला है। श्री केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार लोगों पर जबरदस्ती 20 प्रतिशत इथेनॉल मिला पेट्रोल थोप रही है। जबकि एथनॉल से गाड़ियां बंद हो रही हैं, पाट्‌र्स खराब हो रहे हैं और माइलेज भी 30 प्रतिशत कम आ रहा है। इससे देश भर में लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा है। जब गाड़ियों का 30 प्रतिशत माइलेज कम आ रहा है, तो इथेनॉल मिला पेट्रोल भी 30 प्रतिशत सस्ता होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल के नवनिर्मित फ्रंट ब्लॉक और फिजियोथेरेपी केंद्र का किया उद्घाटन

नई दिल्ली, 03 जुलाई (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को नगर निगम द्वारा निर्मित लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से बने फ्रंट ब्लॉक एवं आधुनिक फिजियोथेरेपी केंद्र का उद्घाटन किया। इस नई स्वास्थ्य अवसंरचना के शुरू होने से क्षेत्र के लगभग 15 से 20 लाख नागरिकों को बेहतर, त्वरित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली का आधार सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था है। इस मौके पर दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवाह, उपमहापौर डॉ. मोनिका पंत वरिष्ठ अधिकारी एवं विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने अस्पताल के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल पिछले लगभग 70 वर्षों से स्थानीय निवासियों और प्रवासी आबादी की सेवा कर रहा है। समय के साथ यहां मरीजों का दबाव

लगातार बढ़ा, जिससे आधुनिक सुविधाओं की कमी महसूस हो रही थी। अब इस नए फ्रंट ब्लॉक और अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी केंद्र के जुड़ने से मरीजों को इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में रेफर करने की जरूरत बेहद कम हो जाएगी। वर्तमान में यह अस्पताल ओपीडी में रोजाना औसतन 600 से 700 मरीजों को सेवाएं दे रहा है, जिसमें अब और विस्तार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक डिजिटलाइजेशन किया है। अब मरीजों के सभी मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखे जा रहे हैं और लंबी लाइनों से राहत देने के लिए डिजिटल अपॉइंटमेंट प्रणाली लागू

की गई है। सभी सरकारी अस्पतालों को एकीकृत डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। इसके माध्यम से एक ऐसा लाइव पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिक सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध आईसीयू बेड की रियल-टाइम जानकारी देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग सहित किसी भी महकमे में यदि कोई भी गड़बड़ी या अनियमितता पाई गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार और नगर निगम मिलकर राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम के पुराने अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए भी सरकार हर संभव वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी।

नवनिर्मित ब्लॉक और अस्पताल की मुख्य विशेषताएं

लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल के नवनिर्मित फ्रंट ब्लॉक में मरीजों और डॉक्टरों की सुविधा के लिए 6-बेड का डे-केयर सेंटर, 12 आधुनिक कंसल्टिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और सीएसआर के सहयोग से अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी केंद्र सहित सभी वातानुकूलित सुविधाएं विकसित की गई हैं। यह पूरी तरह कार्यशील ब्लॉक आधुनिक नैदानिक सुविधाओं, रोगी-अनुकूल आधारभूत संरचना और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जनता को समर्पित करने के लिए तैयार है। अस्पताल में मेडिसिन, स्त्री एवं प्रसूति, नेत्र, ईएनटी, शिशु, त्वचा, दंत, आयुष और फिजियोथेरेपी सहित विभिन्न विशेषज्ञ सेवाओं के साथ डिजिटल एक्स-रे, लैब जांच और सभी आवश्यक दवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

टिप टिप बरसा पानी...पानी में डूबा शहर

कुछ घंटों की बारिश में पानी-पानी हुआ कानपुर : जलभराव, हादसों में डूबे अफसरों, माननीयों के दावे

वेब वार्ता, कानपुर

बादलों से कह दो, जरा सोंच समझ कर बरसे.. कहीं डूब न जाये उम्मीदें संवरने की.. यूं तो यह शायरी इश्क के मिजाज में लिखी गयी थी लेकिन क्या पता था कि अपने शहर पर यह सटीक बैठेगी। लाखों करोड़ों फूंकने के बाद विकास के नाम पर सत्ता से लेकर सरकारी सिस्टम में बैठे अफसरों ने पूरे शहर को ऐसा नर्क में ढकेला है मानसून की पहली बारिश में पूरे शहर में जानलेवा जलभराव हो गया है। लगातार बारिश की चेतावनी के बाद भी नगर निगम के अफसर कागजों के घोड़े दौड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है। वहीं मेट्रों विभागों के खोखले दावों की भी पोल खुल गयी है। जिन विधानसभा में भगवा की लहर सबसे ज्यादा

थी जहां सत्ता के विधायक बैठे है उन्हीं विधानसभा में बारिश ने दावों को धो डाला। सोमवार को हुई हल्की बारिश में ही शहर में कइ जगह जलभराव ने आईना दिखा दिया था कि अभी पूरा सावन भादों बाकी है। लेकिन अफसरों की नींद नहीं टूट रही है। नतीजा मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी मेट्रों, पीडब्लूडी, नगर निगम, जलनिगम कानों में तेल डाले बैठा रहा। शुक्रवार की भोर पहल सवा घंटे की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सबसे ज्यादा खराब स्थित गोविन्द नगर विधानसभा का रही। सुबह लोगों की नींद खुली तो कई दुकानों, और घरो में पानी भर चुका था। जिन महिलाओं को बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना था वह पति के साथ कमरे में भरे पानी को निकालती रही। रावतपुर के रहने वाले आशीष कुमार ने बताया कि वह एक अस्पताल में नौकरी करते है आज जल्दी डयूटी पर जाना था सुबह 6 बजे उठे तो घर में पानी भर चुका था यह देख उनके होश उड़ गये। बाहर निकल कर देखा तो पूरी सड़क लबालब भरी थी। दो घंटे बाद पानी कुछ कम हुआ तो पति पत्नी मिलकर कमरे में भरा पानी निकलने लगे। रावतपुर में कई दुकानों में पानी भरा।

काकादेव कोचिंग मंडी के आसपास स्थित सबसे ज्यादा खराब रही। काकादेव थाने और रावतपुर क्रासिंग की तरफ जाने वाले मार्ग पर भीषण जलभराव रहा। मेट्रों का कार्य चलने के चलते आसपास पानी भरा रहा तो वहीं गढडो में तब्दील हो चुकी सड़कों में कई वाहन पलट गये। शहर के बर्रा, नौबस्ता, चकेरी, जाजमऊ, बिरहाना रोड़, घंटाघर, चमनगंज, बेकनगंज, पुराना कानपुर समेत कई इलाकों में तेज बारिश ने अफसरों के दावों की पोल खोल दी साथ ही ठेकेदारों द्वारा इंटरलॉकिंग, नाला, सफाई, सड़क निर्माण का भ्रष्टाचार भी इस बारिश में बह गया।

काकादेव के अमित त्रिवेदी ने बताया कि सुबह डयूटी के लिये निकले तो हर तरफ जलभराव था इस बीच एक आटो दो फीट गहरे खड्डे में पलट गया। यहां कुछ दिन पूर्व ही जलनिगम ने पाइप लाइन डाली थी। वहीं सीएम ग्रिड योजना से जहां जहां कार्य चल रहा है वहां स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। पूरा दिन अफसर निरीक्षण के नाम खेलते रहे लेकिन बारिश से कैसे जलभराव रूकेगा इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया।

हरदोई में असुरक्षित स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्ती, 5 का चालान, 3 वाहन सीज

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जनपद में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। शासन के निर्देश पर 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक चलाए जा रहे मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत शुक्रवार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) के नेतृत्व में स्कूली वाहनों की सघन जांच की गई।

जांच अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 5 स्कूली वाहनों का चालान किया गया, जबकि 3 वाहनों को संबंधित थानों में निरुद्ध (सीज) कर दिया गया। विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि दक्ष इंटरनेशनल स्कूल (शाहाबाद रोड) के 13, जय विद्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (लखनऊ रोड, खेतुई) के 12 तथा न्यू हाईट्स स्कूल (नानकगंज ग्रांट) के 11 वाहनों के फिटनेस, परमिट, बीमा अथवा प्रदूषण प्रमाणपत्र सहित आवश्यक दस्तावेज वैध नहीं पाए गए। विभाग ने संबंधित विद्यालयों को तत्काल सभी अभिलेख वैध कराने के निर्देश दिए हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि जिन स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा या प्रदूषण प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है, उनके स्वामी तत्काल नवीनीकरण कराएं। ऐसा न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विद्यालय संचालकों और प्रधानाचार्यों से भी अपील की कि वे विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसी भी अनफिट या बिना वैध दस्तावेज वाले वाहन का संचालन न होने दें तथा वाहन स्वामियों को आवश्यक दस्तावेज नवीनीकरण के लिए निर्देशित करें। एआरटीओ ने बताया कि 8 जुलाई से 15 जुलाई तक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम जिले भर में व्यापक अभियान चलाएगी। इस दौरान बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना बीमा, बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र अथवा अन्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर स्कूली बच्चों का परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध चालान, सीज एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश भर में प्रवर्तन विभाग 1 से 15 जुलाई तक चलाएगा सेफ फ्यूचर अभियान

स्कूलों को 7 जुलाई तक का अल्टीमेटम

वेब वार्ता, कानपुर

उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन के द्वारा 1 से 15 जुलाई 2026 तक मिशन सेफ फ्यूचर चलाए जाने का निर्देश दिया है। जिसके अंतर्गत स्कूल वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए विभाग से अधिकारी खुद जायेंगे।

परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश ने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेशभर में मिशन सेफ फ्यूचर अभियान चलाने का आदेश जारी किया। जिसके क्रम में स्कूल वाहनों की फिटनेस समेत अग्नि शमन यंत्रों को बसों और स्कूल में लगवाने की समुचित व्यवस्था करने के सख्त आदेश समूचे प्रदेश में दिया गया है। आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश भर में इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल पर 65162 स्कूल वाहन ऑनबोर्ड हैं। जबकि इनमें से 5647 स्कूली वाहनों की फिटनेस फेल है। और 7418 स्कूली वाहनों के परमिट समाप्त हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहनों के प्रबंधकों को नोटिस व व्यक्तिगत संपर्क,फोन द्वारा सचेत किया जाएगा। इसके साथ ही 7 जुलाई तक शतप्रतिशत स्कूलों को वाहनों की फिटनेस करा कर परमिट वैध कराने के लिए नोटिस जारी की गई।

आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम हर स्कूल में जाकर वाहनों की वस्तुस्थिति का भौतिक अवलोकन करेगी। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। और देश के भविष्य के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करना परिवहन विभाग का दायित्व है।

संक्षिप्त वार्ता

आपसी विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, एक गंभीर घायल

वेब वार्ता, देवरिया

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक गाँव नौतन हथिया गढ़ में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट के दौरान युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। जिसका उपचार महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की इमरजेंसी में चल रहा है। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की सुबह रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के हथिया गढ़ गाँव में दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया। जिसमें एक पक्ष से युवक ने चाकू से हमला कर दिया। जिसमें राजू शर्मा उम्र 30 वर्ष पुत्र दशरथ व सुधीर शर्मा उम्र 37 वर्ष पुत्र रामनरेश निवासी नौतन हथियागढ़ थाना रामपुर कारखाना गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए परिजन महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कालेज की इमरजेंसी ले आए जहां चिकित्सकों ने राजू शर्मा को मृत घोषित कर दिया वही सुधीर का गंभीर अवस्था में उपचार चल रहा है।

मकान का छज्जा गिरने से महिला की मौत, तीन मासूम बच्चे घायल

वेब वार्ता, देवरिया

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मकान का छज्जा गिरने से गौरीबाजार क्षेत्र में रिश्तेदारी में आई एक महिला की मौत हो गई।जबकि तीन मासूम बच्चे मामूली रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार देवरिया जिले के सुरौली थाना क्षेत्र के ग्राम मंझगांवा निवासी 45 वर्षीय फूला देवी रिश्तेदारी में गौरीबाजार थाना क्षेत्र स्थित सीताराम गोड़ के घर आई थीं। बगल में रहने वाले बांसफोर परिवार टिनशेड डालकर रह रहे थे। शुक्रवार रात करीब नौ बजे अचानक पास स्थित गौरीशंकर जायसवाल के मकान का छज्जा भरभराकर गिर पड़ा। इसकी चपेट में फूला देवी समेत तीन बच्चे आ गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गौरीबाजार पहुंचाया। चिकित्सकों ने फूला देवी की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, देवरिया रेफर कर दिया। जहां देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे में फूला देवी की चार वर्षीय पुत्री श्री, तीन वर्षीय पुत्र आदित्य तथा दो वर्षीय वीर को भी चोटें आईं।

यूपीटीईटी परीक्षा: डीएम-एसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण

निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण परीक्षा के दिए निर्देश

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी)-2026 के दूसरे दिन प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने संयुक्त रूप से राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, हरदोई का निरीक्षण कर परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया, सीसीटीवी निगरानी तथा अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोग एवं शासन की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक अभ्यर्थी की निर्धारित मानकों के अनुरूप सघन जांच के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाए। साथ ही परीक्षा के दौरान सभी सीसीटीवी कैमरे निरंतर संचालित रहें तथा उनकी नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने सेक्टर एवं जोनल अधिकारियों को लगातार भ्रमणशील रहकर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने और किसी भी प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनपद में यूपीटीईटी-2026 की परीक्षा प्रशासन की कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं।

रखी जायेगी सतर्क निगरानी

इस दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखी जाए।

हादसे बढ़े, सुविधा नहीं: एक पोस्टमार्टम हाउस के भरोसे पूरा ललितपुर

मौत के बाद भी इंतजार... एक पोस्टमार्टम हाउस के सहारे पूरा ललितपुर

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में सड़क दुर्घटनाओं, आत्महत्या, हत्या और अन्य अप्राकृतिक मौतों के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम जैसी बुनियादी सुविधा आज भी संसाधनों की कमी से जूझ रही है। पूरे जनपद में केवल एक पोस्टमार्टम हाउस होने के कारण मृतकों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए कई बार दो से तीन दिन तक इंतजार करना पड़ता है।

जनपद के दूरस्थ विकासखंड मड़ावरा, महरौनी, तालबेहट, जखौरा, बार और बिरधा सहित सैकड़ों गांवों से शवों को जिला मुख्यालय तक लाने में ही कई घंटे लग जाते हैं। इसके बाद पुलिस की वैधानिक कार्रवाई, पंचनामा, पोस्टमार्टम की प्रतीक्षा और चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी होने में लंबा समय लग जाता है। यदि एक ही दिन में कई शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंच जाएं तो परिजनों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।

स्थिति यह है कि शोक में डूबे परिवार अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार के लिए भी दो-दो और तीन-तीन दिन तक इंतजार करने को मजबूर हो जाते हैं। इस दौरान दूरदराज से आए परिजनों को जिला मुख्यालय में रुकना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ के साथ मानसिक पीड़ा भी बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में यह समस्या और अधिक गंभीर रूप ले लेती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भौगोलिक दृष्टि से बड़ा जनपद होने के बावजूद केवल एक पोस्टमार्टम हाउस पूरे जिले की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। वर्षों से अतिरिक्त पोस्टमार्टम हाउस की मांग उठती रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। लोगों का मानना है कि यदि महरौनी या तालबेहट क्षेत्र में एक अतिरिक्त पोस्टमार्टम हाउस स्थापित किया जाए तो जिले के आधे से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत मिल सकती है और पोस्टमार्टम प्रक्रिया भी तेज होगी।

सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने राज्य सरकार से जनपद में अतिरिक्त पोस्टमार्टम केंद्र स्थापित करने, आवश्यक चिकित्सकों की तैनाती करने और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यह केवल स्वास्थ्य सुविधा का विषय नहीं, बल्कि शोकाकुल परिवारों की संवेदनाओं और सम्मानजनक अंतिम विदाई से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। जनपद में लगातार बढ़ रहे हादसों और अप्राकृतिक मौतों के मामलों के बीच अब लोगों की नजर शासन और प्रशासन पर टिकी है। सवाल यह है कि आखिर कब तक पूरा ललितपुर एकमात्र पोस्टमार्टम हाउस के सहारे चलता रहेगा और शोकाकुल परिवार अपने प्रियजनों की अंतिम विदाई के लिए व्यवस्था का इंतजार करते रहेंगे।

जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने कहा...

जनपद में पोस्टमार्टम सुविधा को लेकर लोगों को हो रही असुविधा का संज्ञान लिया गया है। अतिरिक्त पोस्टमार्टम हाउस की आवश्यकता के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजने एवं आवश्यक पत्राचार की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। शासन स्तर से स्वीकृति मिलने पर आमजन को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

ग्रामीण चौपाल में सीडीओ का सख्त रुख, स्कूल, अस्पताल और राशन व्यवस्था की परखी हकीकत

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल ने शुक्रवार को विकासखंड सांडी की ग्राम पंचायत आदमपुर में आयोजित ग्रामीण चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। चौपाल के दौरान उन्होंने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत भी जानी। चौपाल में भानु मिश्रा के घर के पास लगे हैंडपंप को रीबोर योग्य पाए जाने पर सीडीओ ने तत्काल रीबोर कराने के निर्देश दिए। वहीं सांडी देहात के कोटेदार रामशंकर के खिलाफ निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरण की शिकायत मिलने पर जिला पूर्ति अधिकारी को जांच कर दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आदमपुर के मजरा पुरवा में नाली की सफाई न होने की शिकायत पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को जांच कर जिम्मेदार सफाईकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा गया।

वेनेजुएला से शव मंगाने के लिए मुंबई में सात दिन तक जूझा परिवार

वेब वार्ता,देवरिया। वेनेजुएला में मालवाहक पोत पर कार्यरत रहे देवरिया के चालक दल के सदस्य (फिटर) राकेश चौहान की मृत्यु के बाद उनका शव भारत मंगाने के लिए परिवार को 28 दिनों तक संघर्ष करना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि सूचना मिलने के बाद वे सात दिन तक मुंबई में कंपनी के कार्यालयों और अधिकारियों के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें गुमराह किया जाता रहा।पहले एक सप्ताह में शव भारत पहुंचाने का भरोसा दिया गया। फिर बार-बार समय बढ़ाया गया। बाद में 15 दिन और लगने की बात कहने पर परिवार को मजबूर होकर गांव लौटना पड़ा। चार जून को शव घर पहुंचा, । जिसके बाद पोस्टमार्टम में मस्तिष्क, हृदय, दोनों फेफड़े, यकृत, दोनों गुर्दे, प्लीहा आदि अंग गायब मिलने से मामला और गंभीर हो गया है। मृतक के पिता रामदेव चौहान ने बताया कि सात मई को कंपनी ने पहले सूचना दी कि राकेश जहाज पर दुर्घटना में घायल हो गए हैं और उनका उपचार चल रहा है। कुछ देर बाद हालत गंभीर होने और फिर हृदयाघात से मृत्यु की सूचना दी गई।

कंपनी के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया था कि एक सप्ताह के भीतर शव भारत पहुंच जाएगा। इसी उम्मीद में वह छोटे बेटे 29 वर्षीय मुकेश व बहू रंजना के साथ मुंबई पहुंचे और सात दिन तक वहीं रुके रहे। इस दौरान कंपनी की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई और बाद में बताया गया कि शव आने में 15 दिन और लगेंगे। इसके बाद उन्हें गांव लौटना पड़ा।

परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद से कंपनी के प्रतिनिधि उन पर लगातार दबाव बनाते रहे। मुंबई में कुछ सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर पहले शव को समुद्र में फेंक देने की धमकी दी गई और अब मामला उठाने पर किसी भी प्रकार का भुगतान या सहायता नहीं मिलने की बात कही जा रही है।उनका आरोप है कि कंपनी ने अब तक मृतक राकेश का मोबाइल फोन व अन्य व्यक्तिगत सामान भी नहीं लौटाया है, जबकि पहले दावा किया गया था कि शव के साथ पूरा सामान भेज दिया जाएगा। चार जून को शव घर पहुंचने के बाद पांच जून को डीएम के आदेश पर पोस्टमार्टम कराया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मस्तिष्क, हृदय, दोनों फेफड़े, यकृत, दोनों गुर्दे, प्लीहा, अग्न्याशय, आमाशय, थायरायड ग्रंथि, हायाइड अस्थि, स्वरयंत्र और श्वासनली सहित कई प्रमुख आंतरिक अंग अनुपस्थित मिलने का उल्लेख है। मृतक की पत्नी रंजना का कहना है कि यदि दोबारा पोस्टमार्टम नहीं कराया गया होता तो परिवार को कभी पता ही नहीं चलता कि शव से कई अंग निकालकर भारत भेजा गया था।

रंजना ने केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों को भेजे गए प्रार्थना-पत्र में आरोप लगाया है कि कंपनी घटना से जुड़ी सही जानकारी नहीं दे रही है। सेवा अनुबंध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप परिवार को मिलने वाले वैधानिक अधिकार व सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने कंपनी, जहाज प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। प्रार्थना-पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि राकेश के व्यक्तिगत सामान की प्राप्ति संबंधी रसीद पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने इसकी फोरेंसिक जांच कराने, परिवार को सभी वैधानिक देयकों का भुगतान सुनिश्चित कराने तथा पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) या किसी अन्य स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

भर्ती और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में हरदोई के बीएसए डॉ. अजीत सिंह निलंबित

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई/लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने हरदोई के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. अजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 61 अभ्यर्थियों की भर्ती, नियुक्ति प्रक्रिया तथा वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों की जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद की गई है।

उत्तर प्रदेश शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-1
लखनऊ : दिनांक 02 जुलाई, 2026
कार्यालय-आदेश

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिलाधिकारी हरदोई की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही तथा पेंशन, चयन वेतनमान और अन्य वित्तीय मामलों में अनियमितताओं की ओर संकेत किया है। जांच में इन आरोपों के प्रथम दृष्टया प्रमाण मिलने के आधार पर शासन ने डॉ. अजीत सिंह को निलंबित करने का निर्णय लिया। निलंबन अवधि के दौरान डॉ. अजीत सिंह को शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। शासन ने विभागीय जांच के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ मंडल को जांच अधिकारी नामित किया है। अब जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। शासन के इस निर्णय से बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की अंतिम पुष्टि और आगे की कार्रवाई तय होगी।

कप्तानगंज में युवक की संदिग्ध मौत, चार युवकों पर हत्या का आरोप

वेब वार्ता, कुशीनगर। घायलावस्था में मिले बहन के घर आए युवक की उपचार के दौरान मौत होने पर परिजन संग ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार की रात नौ बजे शव लेकर कप्तानगंज थाने पर पहुंचे और हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस के आश्वासन पर आधे घंटे बाद माने तो शव लेकर वापस लौटे।

पुलिस के अनुसार महाराजगंज के भिटौली थाने के गांव सोहरौना राजा निवासी 18 वर्षीय प्रमोद साहनी अपनी बहन के घर कप्तानगंज थाना के पचार गांव सोमवार की शाम छह बजे आए।मिलने के बाद गांव के ही चौराहे पर मीट खरीदने चले गए। काफी देर बाद भी जब वापस नहीं लौटे तो परिजन तलाश करने निकले तो चौराहे के समीप ही एक पुलिया के समीप घायलावस्था में सड़क किनारे बेसुध मिले।प्राथमिक उपचार के बाद देर रात उच्चीकृत स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज से मेडिकल कालेज अस्पताल गोरखपुर रेफर कर दिया गया। वहां उपचार के दौरान बुधवार को मौत हो गई। रात को शव एंबुलेंस से गांव पहुंचा तो परिजन पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए शव लेकर सीधे थाने पहुंच गए।बहनोई गुनारी साहनी ने गांव के ही चार युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर सौंप मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। कप्तानगंज थानाध्यक्ष धीरेंद्र राय ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए समझा बुझाकर वापस भेजा।

इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

महत्वपूर्ण ख़बर

स्विफ्ट टेलीस्कोप को बचाने का 30 अरब डॉलर खर्च करेगा नासा

वाशिंगटन। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने अंतरिक्ष में अपने स्विफ्ट टेलीस्कोप को बचाने के लिए एक बचाव अभियान शुरू किया है। नासा का यह स्विफ्ट टेलीस्कोप अब पृथ्वी पर गिरने की कगार पर है। अंतरिक्ष में लगभग दो दशकों से ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहे इस महत्वपूर्ण बूढ़े योद्धा को बचाने में लगभग 30 अरब डॉलर का अनुमानित खर्च आएगा। 2004 में लॉन्च किया गया स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी, ब्रह्मांड में गामा-रे बर्स्ट्स जो सबसे शक्तिशाली विस्फोट माने जाते हैं और अन्य जटिल ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करता है। यह उपग्रह लगातार नासा के वैज्ञानिकों को मूल्यवान और आवश्यक जानकारियां प्रदान करता रहा है, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजें संभव हो पाई हैं। यही कारण है कि नासा इसे खोना नहीं चाहता है और इस पर इतना बड़ा निवेश करने को तैयार है। स्विफ्ट टेलीस्कोप अपनी उम्र के कारण अब नीचे की ओर गिरना शुरू हो गया है। इसके सौर पैनलों की बैटरी कमजोर हो गई है, और तेज सौर गतिविधि ने भी इसकी कक्षा को प्रभावित किया है।

सिंधु जल संधि पर भारत अपने रुख पर कायम

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की आपत्तियां खारिज : हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पर भारत ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है।

भारत ने हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (सीओए) की कार्यवाही और उसके एकतरफा फैसले को मानने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया है कि संधि के प्रावधानों की अनदेखी कर शुरू की गई किसी भी प्रक्रिया का कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत के इस रुख के बाद पाकिस्तान के कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का कहना है कि सिंधु जल संधि में विवादों के समाधान के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित है। नई दिल्ली के अनुसार, तकनीकी विवादों पर पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति का प्रावधान है और उसके बाद ही अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। भारत का आरोप है कि इस प्रक्रिया का पालन किए बिना समानांतर मध्यस्थता शुरू की गई, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के महानिदेशक सुजान चिनॉय ने अपने एक विश्लेषण में कहा है, कि भारत ने संधि को स्थगित करने से पहले विश्व बैंक से न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करने का अनुरोध किया था। वहीं पाकिस्तान

ने समानांतर रूप से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जरिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। तत्कालीन विश्व बैंक अध्यक्ष ने दोनों प्रक्रियाओं को साथ चलाने की मंजूरी दी, जिसे भारत ने संधि की मूल भावना के विपरीत बताया और इस प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया।

भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसका विरोध कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की वैधानिकता को लेकर है, न कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (पीसीए) जैसी संस्था के अस्तित्व को लेकर। सरकार का कहना है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नियम-आधारित व्यवस्था का सम्मान करती है, लेकिन प्रक्रियाओं का पालन भी उतना ही आवश्यक है। विश्लेषकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे उदाहरण पहले भी सामने आए हैं, जब विभिन्न देशों ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक या मध्यस्थता संबंधी फैसलों को स्वीकार नहीं किया। वहीं भारत ने 2014 में बंगाल की खाड़ी समुद्री सीमा विवाद में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) के फैसले को स्वीकार कर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित की थी। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच आगे की कूटनीतिक एवं कानूनी प्रक्रिया पर दोनों देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है।

मानसून का रौद्र रूप

जम्मू-कश्मीर में फिर बादल फटे, बारिश से बदरीनाथ हाईवे बंद

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के कई हिस्सों में लंबे समय से जारी भीषण गर्मी से राहत लेकर आया है, लेकिन इसके साथ ही यह अपने पीछे तबाही का मंजर भी छोड़ गया है। बारिश से पंजाब, हरियाणा और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को भीषण गर्मी और चिपचिपाती उमस से बड़ी राहत मिली है। लेकिन, जम्मू-कश्मीर में लगातार दूसरे दिन बादल फटने से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है और एक सड़क बह गई है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण बदरीनाथ हाईवे साढ़े 11 घंटे बंद रहा और आठ हजार से ज्यादा श्रद्धालु रास्ते में जहां-तहां फंसे रहे। भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश में भी कोहराम मचा रखा है। राज्य में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के चलते 46 सड़कें बंद हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, हरियाणा और पंजाब में रुक-रुक कर बौछारें पड़ीं, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत मिली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी मानसून के पहुंचने के बाद बारिश हुई है, जिससे गर्मी और धूल भरी आंधी से लोगों को राहत मिली है।

भारत-जापान का रिश्ता बदलती वैश्विक राजनीति और चीनी चुनौती के बीच हो रहा मजबूत

नई दिल्ली। भारत और जापान की दोस्ती करीब डेढ़ हजार साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत और सात दशक से भी ज्यादा लंबी रणनीतिक साझेदारी की मिसाल है। जब दुनिया के कई देश बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच अपने साझेदार बदल रहे हैं, तब भारत और जापान का विश्वास गहरा होता जा रहा है।

बदलती वैश्विक राजनीति और चीन की बढ़ती चुनौती के बीच, यह रिश्ता मजबूत हो रहा है, जिसकी झलक पीएम मोदी और जापान की पीएम सनाए ताकाइची के शिखर सम्मेलन में देखने को मिलेगी।

यह साझेदारी सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद अहम है। इस गहरी दोस्ती की जड़ें छठी शताब्दी में भारत से चीन और कोरिया के रास्ते जापान पहुंचे बौद्ध धर्म में निहित हैं, जिसने जापानी समाज और संस्कृति को प्रभावित किया। आज भी जापान में भगवान बुद्ध के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। आधुनिक युग में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत

जापान के पुनर्निर्माण का समर्थन करने वाले शुरूआती देशों में से था। 1952 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए और 2014 में इसे विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा मिला, जिसने आर्थिक, रक्षा और तकनीकी सहयोग को नई दिशा दी। यही कारण है कि आज भारत और जापान को एशिया की सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारियों में गिना जाता है।

जापान ने भारत के विकास को केवल कारोबारी नजरिए से नहीं देखा, बल्कि दीर्घकालिक सहयोग की नीति अपनाई है। जापान की आधिकारिक विकास सहायता भारत की सबसे बड़ी विदेशी विकास सहायता में शामिल है। भारत भी जापान के लिए केवल एक बड़ा बाजार नहीं है, दुनिया की सबसे युवा आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था ने भारत को जापान के लिए एक स्वाभाविक साझेदार बना दिया है। पिछले कुछ सालों में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने भारत और जापान के रिश्तों को नई मजबूती दी है। दोनों देश फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक की अवधारणा का समर्थन करते हैं और क्वाड समूह के सक्रिय सदस्य हैं।

भारत में 1400 से ज्यादा जापानी कंपनियां सक्रिय हैं, जो ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी तक कई क्षेत्रों में हजारों रोजगार पैदा कर रही हैं। मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा और हिताची जैसे बड़े ब्रांड भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। जापान अब चीन पर निर्भरता कम करने और विकल्प के रूप में भारत को अपना सबसे भरोसेमंद विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुछ चुनौतियां जैसे व्यापार की पूरी क्षमता का न मिलना या नियामकीय प्रक्रियाओं की जटिलता मौजूद हैं, लेकिन दोनों देशों की सरकारें इन्हें दूर करने पर लगातार काम कर रही हैं। साल 2027 में भारत और जापान अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे करेंगे, और यह दोस्ती आने वाले समय में एशिया की स्थिरता और वैश्विक विकास की एक मजबूत धुरी बनी रहेगी।

तिब्बत में मासूमों को चीनी संस्कृति में ढाल रहा ड्रैगन

नई दिल्ली। चीन, तिब्बत में एक गहरे और खतरनाक खेल को अंजाम दे रहा है, जिसका उद्देश्य तिब्बती संस्कृति, भाषा और पहचान को हमेशा के लिए मिटाना है। इस रणनीति का मुख्य निशाना मासूम बच्चे हैं, जिन्हें उनके माता-पिता से जबरन अलग कर चीनी संस्कृति में ढालने का प्रयास किया जा रहा है। कूटनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने एक लेख में इस भयावह स्थिति का खुलासा किया है, जिसके बारे में 67 साल पहले भारत आए दलाई लामा ने भी शायद कल्पना नहीं की होगी।

चेलानी के अनुसार, बीते दस वर्षों में चीन ने दस लाख से अधिक तिब्बती बच्चों को जबरदस्ती उनके माता-पिता से छीनकर बोर्डिंग स्कूलों में भेज दिया है। इनमें से ज्यादातर बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी उम्र चार या पांच साल से भी कम है, और वे साल में ज्यादातर वक्त घर से दूर ही रहते हैं। चीन इन स्कूलों को बच्चों के डेवलपमेंट का मॉडल बताता है, लेकिन हकीकत में ये जबरन उन पर अपनी संस्कृति थोपने के हथियार हैं। इनका मकसद बच्चों को उनकी भाषा, धर्म और सांस्कृतिक विरासत से अलग करना है, ताकि वे तिब्बत की पहचान छोड़कर चीनी नागरिकों की तरह हो जाएं। इन बच्चों को सिखाया जाता है कि तिब्बत में जो कुछ वे सीखते हैं, वह सब कुछ पुराना हो चुका है, और उन्हें बताया जाता है कि उनकी पहचान चीन से है। साफ है कि इससे नई पीढ़ी अपनी जड़ों से कटती जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने उपनिवेशवाद के दौरान लोगों की संस्कृति को छीन लिया था।

यह रणनीति सिर्फ सांस्कृतिक दमन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी भू-राजनीतिक परिणाम भी हैं। तिब्बत को अक्सर दुनिया की छत कहा जाता है, और उस पर चीन का नियंत्रण दक्षिण एशिया की भू-राजनीति और शक्ति संतुलन को गंभीर रूप से बदल सकता है। तिब्बत पर मजबूत पकड़ से चीन हिमालय पर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकता है और एशिया में बहने वाली अधिकांश नदियों के पानी के बहाव पर नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि उनका उद्गम तिब्बत में है। इसी तिब्बत में चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है और वहाँ के खनिजों को तेजी से निकाल रहा है। इन्हीं वजहों से चीन तिब्बत पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर रहा है, ताकि भविष्य में कोई उसे चुनौती न दे पाए। अपनी इस चाल को और पुख्ता करने के लिए चीन एक और बड़ा गेम खेल रहा है। वह तिब्बत का नाम ही मिटा रहा है और उसकी जगह शिजांग शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। शिजांग चिंग राजवंश के समय का एक नाम है, जिसका अर्थ है खजाने से भरी धरती। हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के कुछ संग्रहालय भी चीन की बात मानने लगे हैं और वे भी अब तिब्बत की जगह शिजांग लिखने लगे हैं, खासकर पश्चिमी देशों में यह खेल खूब चल रहा है। इससे चीन को अपनी नीति को वैश्विक वैधता देने में मदद मिल रही है। भारत को भी इस सांस्कृतिक नरसंहार और नाम बदलने की चाल को लेकर चिंतित होना चाहिए, क्योंकि यह न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है बल्कि क्षेत्र की भू-राजनीतिक स्थिरता के लिए भी एक गंभीर खतरा है।

दो हंपबैक व्हेल ने 15 हजार किमी यात्रा कर बनाया रिकॉर्ड

लंदन। ताजा शोध ने समुद्री जीव विज्ञान की कई पुरानी धारणाओं को चुनौती दे दी है। दो हंपबैक व्हेल ने ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के बीच लगभग 15 हजार किलोमीटर लंबी समुद्री यात्रा पूरी कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे पहले किसी भी व्हेल के इतनी अधिक दूरी तय करने का प्रमाण नहीं मिला था। आमतौर पर हंपबैक व्हेल भोजन और प्रजनन के लिए मौसम के अनुसार लंबी यात्राएं करती हैं। वे गर्मियों में ठंडे समुद्री क्षेत्रों में भोजन जुटाती हैं और सर्दियों के दौरान प्रजनन के लिए गर्म समुद्री इलाकों का रुख करती हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से ब्राजील तक महासागर पार करना बेहद दुर्लभ माना जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस रिकॉर्ड ने यह संकेत दिया है कि इन व्हेलों की आवाजाही पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो सकती है। समुद्री जीवों की गतिविधियों पर नजर रखना आसान नहीं होता। इस अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने पिछले चार दशकों में एकत्र की गई 19 हजार से अधिक हंपबैक व्हेल की तस्वीरों का विश्लेषण किया। इन तस्वीरों को विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और नागरिक वैज्ञानिकों ने मिलकर संकलित किया था।

समुद्री सतह पर जून माह का अब तक का सबसे अधिक तापमान रिकार्ड

नई दिल्ली। 21 जून को वैश्विक समुद्री सतह का औसत तापमान 20.86 डिग्री सेल्सियस यानी 69.5 डिग्री फॉरेनहाइट तक पहुंच गया। यूरोप की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के नए आंकड़ों के अनुसार, यह जून महीने का अब तक का सबसे अधिक तापमान है और पिछले साल बने रिकॉर्ड को भी इसने पीछे छोड़ दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तापमान बढ़ने की यही रफ्तार बनी रही, तो आने वाले महीनों में और भी बड़े रिकॉर्ड टूट सकते हैं। इसका असर सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के मौसम, कृषि और जनजीवन पर भी व्यापक रूप से दिखाई देगा। महासागरों का बढ़ता तापमान केवल एक वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन की गंभीर तस्वीर भी पेश करता है। समुद्र पृथ्वी की अतिरिक्त गर्मी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अपने भीतर समाहित करते हैं, जिससे वे ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब जब वही समुद्र लगातार गर्म हो रहे हैं, तो उनका संतुलन भी बिगड़ने लगा है, जिससे कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, अल नीनो की शुरूआत और

मानव गतिविधियों से बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने मिलकर इस स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है। यही कारण है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर वैश्विक मौसम चक्र तक पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट के अनुसार, कोपरनिकस मरीन सर्विस, जिसका संचालन मेरकाटॉर ओसन इंटरनेशनल करता है, ने भी इसी तरह के आंकड़े जारी किए हैं।

इस संस्था के अनुसार 21 जून को समुद्र की सतह का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले साल के रिकॉर्ड से लगभग 0.18 डिग्री फॉरेनहाइट अधिक है। अलग-अलग संस्थाओं के समान निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि महासागरों की गर्मी अब सामान्य उतार-चढ़ाव से कहीं आगे निकल चुकी है। वैज्ञानिक इसे वैश्विक जलवायु संकट का बड़ा संकेत मान रहे हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के समुद्री वैज्ञानिक माइकल मेरिडिथ ने कहा कि समुद्री सतह का तापमान बढ़ना कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, क्योंकि महासागर सालों से अतिरिक्त गर्मी को अपने भीतर समेटते आ रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से तापमान बढ़ रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। वहीं, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के निदेशक कार्लो बुओनटेम्पो ने चेतावनी दी कि मौजूदा हालात यह संकेत दे सकते हैं कि दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है, जहां पहले कभी अनुभव नहीं किए गए हालात सामने आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अल नीनो के प्रभाव के साथ आने वाले महीनों में और भी नए रिकॉर्ड बन सकते हैं।

वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो समुद्री जैव विविधता को लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है और समुद्र का बढ़ता तापमान समुद्र स्तर में भी वृद्धि करेगा, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि जून का यह रिकॉर्ड अस्थायी है या आने वाले सालों की नई वास्तविकता। लेकिन इतना तय है कि लगातार टूटते तापमान रिकॉर्ड दुनिया के लिए गंभीर चेतावनी हैं। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और अल नीनो जैसे प्राकृतिक कारकों का संयुक्त प्रभाव पृथ्वी को ऐसे मोड़ पर ले जा रहा है, जहां जलवायु परिवर्तन का असर पहले से कहीं अधिक दिखाई देगा।

क्षेत्रों को छोड़ने पर हो रही हैं मजबूर

महासागरों का तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा असर वैश्विक मौसम पर पड़ता है। जब समुद्र गर्म होते हैं, तो वे वातावरण में अधिक गर्मी और नमी छोड़ते हैं। इससे भीषण हीटवेव, अधिक ताकतवर चक्रवात, अत्यधिक बारिश और बाढ़ जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गर्मी जितनी अधिक होगी, मौसम उतना ही अस्थिर और खतरनाक होता जाएगा। यही वजह है कि दुनिया के कई हिस्सों में हाल के वर्षों में चरम मौसम की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। समुद्र का बढ़ता तापमान समुद्री जीवन के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। गर्म पानी की वजह से कोरल रीफ (प्रवाल भित्तियां) बड़े पैमाने पर सफेद पड़ रहे हैं, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। इससे हजारों समुद्री जीवों का प्राकृतिक आवास खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कई समुद्री प्रजातियां अपने पारंपरिक क्षेत्रों को छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं।

भारत में वैज्ञानिक रूप से दर्ज जीव-जंतुओं की संख्या बढ़कर 1,05,953 हुई

देश में 483 जीव प्रजातियां खोजी गईं, नई खोजों में केरल नंबर वन पर

नई दिल्ली। भारत की जैव विविधता का दायरा और बढ़ गया है। 2025 के दौरान देश में 483 ऐसी जीव प्रजातियां खोजी गईं जिन्हें विज्ञान ने पहली बार दर्ज किया, जबकि 226 प्रजातियां ऐसी मिलीं जो पहली बार भारत में रिकॉर्ड की गईं यानी कुल 709 नए जीवों के रिकॉर्ड देश के जैव विविधता डेटाबेस में जुड़े हैं। इसके साथ ही भारत में वैज्ञानिक रूप से दर्ज जीव-जंतुओं की कुल संख्या बढ़कर 1,05,953 हो गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 111वें स्थापना दिवस पर कोलकाता में आयोजित एनिमल टैक्सोनॉमी समिट-2026 में इसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एनिमल डिस्कवरीज-2025, प्लांट डिस्कवरीज-2025 और फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट वर्जन 3.0 जारी की। यादव ने कहा कि किसी भी जीव की पहचान और वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण के बिना उसका संरक्षण संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि दुनिया के कुल भूभाग का केवल 2.4फीसदी

हिस्सा भारत के पास है, लेकिन यहां दुनिया की 7-8फीसदी दर्ज प्रजातियां पाई जाती हैं। यही वजह है कि भारत दुनिया के 17 सबसे जैव विविध देशों में शामिल है।

उन्होंने बताया कि केरल में सबसे ज्यादा 98 नई प्रजातियां, पश्चिम बंगाल में 76, कर्नाटक में 67 और अरुणाचल प्रदेश में 65 नई प्रजातियां दर्ज की गईं। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण की उपलब्धियां भी गिनाईं। उनके मुताबिक 2014 के बाद देश में टाइगर रिजर्व की संख्या 47 से बढ़कर 58 हो गई है। एशियाई शेरों की संख्या 523 से बढ़कर 891 पहुंच गई। वहीं, रामसर साइट्स 24 से बढ़कर 100 और ईको-सेंसिटिव जोन करीब 1,865 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 68,500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो गए हैं।

इस अवसर पर पैलियोइंडिया पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देशभर में मिले 5,000 से ज्यादा जीवाश्म की जानकारी उपलब्ध होगी। इससे वैज्ञानिकों के साथ-साथ आम लोग भी जीवाश्मों और जैव विविधता से जुड़ी जानकारी आसानी से देख सकेंगे। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक को जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित 111 घंटे के राष्ट्रीय हैकाथॉन के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।

66 अरब में चीन ने पहाड़ काट दौड़ा दी 350 किमी/घंटा की रफ्तार से बुलेट ट्रेन

बीजिंग। चीन ने अपने विशाल हाई-स्पीड रेल नेटवर्क में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली नई बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की है। यह परियोजना देश के उत्तर-पश्चिमी और मध्य हिस्सों को जोड़ते हुए दुर्गम चिनलिंग पर्वतों से होकर गुजरती है, जिसे चीन के इंजीनियरिंग कौशल का एक और बड़ा प्रमाण माना जा रहा है। इस नई बुलेट ट्रेन सेवा की शुरूआत मंगलवार को शीआन ईस्ट रेलवे स्टेशन से बुलेट ट्रेन जी-3966 के रवाना होने के साथ हुई। यह हाई-स्पीड रेल लाइन शान्शी प्रांत की राजधानी शीआन को हुबेई प्रांत के शियान शहर से जोड़ती है। इस 257 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के चालू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से भी अधिक कम हो गया है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क में क्रांतिकारी सुधार आएगा। इसके अतिरिक्त, यह नई लाइन पहले से मौजूद वुहान-शियान हाई-स्पीड रेल से भी जुड़ती है, जिससे अब शीआन से वुहान तक का सफर मात्र 2 घंटे 41 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। यह गति और दक्षता चीन की परिवहन अवसंरचना को वैश्विक स्तर पर एक नई ऊँचाई पर ले जाती है। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसका चुनौतीपूर्ण भौगोलिक मार्ग है। यह रेल लाइन विशाल चिनलिंग पर्वतों और हानजियांग नदी के बीच से होकर गुजरती है। इसी वजह से पूरे रूट का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विशाल पुलों और लंबी सुरंगों पर बनाया गया है। परियोजना के मुख्य डिजाइनर माओ लेई ने बताया कि यह रेल मार्ग एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संग्रहालय से होकर गुजरता है, और इसलिए इसे बनाना इंजीनियरों के लिए बेहद मुश्किल भरा काम था।

ताजा खबर

संक्षिप्त

रायपुर कलेक्टर ने रायपुर निगम के 11 नव नामांकित पार्षद एल्डरमेन को पद की शपथ दिलाई

रायपुर। छत्तीसगढ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा रायपुर नगर पालिक निगम में 11 नामांकित पार्षद एल्डरमेन सर्वश्री रामकिंकर सिंह, विनय ओझा, मनीष करडभुजे, मित्रसेन धीमान, राजू राधवानी, गोपाल सोना, बी. निवास राव, अनिल सोनकर, गोपी साहू, विक्रम सिंह ठाकुर, ऋषि साहू को आज रायपुर जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने रायपुर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पद की शपथ दिलवायी। सभी 11 नामांकित पार्षदो, एल्डरमेनो ने पद की ईश्वर के नाम सत्यनिष्ठा की शपथ ली।

बस्तर में 63, बिलासपुर में 197 और दुर्ग में 146 एल्डरमैनों की नियुक्ति

रायपुर। रायपुर और सरगुजा संभाग के बाद राज्य सरकार ने बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के नगरीय निकायों में भी एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) नियुक्त कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मनोनीत पार्षदों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। बस्तर संभाग में 63, बिलासपुर संभाग में 197 और दुर्ग संभाग में 146 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। रायपुर और सरगुजा संभाग के विभिन्न नगरीय निकायों में 254 एल्डरमैनों की नियुक्ति हुई थी। इन नियुक्तियों के साथ ही प्रदेश के सभी पांचों संभागों के नगरीय निकायों में मनोनीत पार्षदों की तैनाती की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

किसान खेती-बाड़ी की समुचित योजना बनाए: सीएम साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि अल नीनो के प्रभाव के कारण इस वर्ष मानसून सामान्य से कमजोर रहने की संभावना है। ऐसे में किसानों को मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खेती-बाड़ी की समुचित योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को लगातार आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग ने पहले ही अल नीनो के कारण मानसून कमजोर रहने की संभावना से अवगत करा दिया है। इसे देखते हुए किसानों को फसल चयन, बुआई और अन्य कृषि कार्यों की योजना मौसम के अनुरूप बनानी चाहिए, ताकि संभावित प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव कम किया जा सके।

आनंद मेला- एक कदम स्वावलंबन की ओर...

रायपुर। केंसर मरीजों की मदद एवं सहयोग हेतु अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल रायपुर शाखा द्वारा एम जी रोड स्थित जैन दादाबाड़ी में रविवार 5 जुलाई को एक कदम स्वावलंबन की ओर का आयोजन किया जा रहा है. रायपुर शाखा की अध्यक्षा श्रीमती प्रमिला बरलोटा ने बताया कि केंसर मरीजों की सहायता एवं सहयोग हेतु मनोरंजन एवं समाज सेवा के लिए आनंद मेले का आयोजन किया जा रहा है।

21 से 23 अगस्त तक लगेगी विशेष लोक अदालत

रायपुर। न्याय को सरल, सुलभ और आमजन तक पहुंचाने तथा आपसी सहभागिता और सहमति के माध्यम से न्याय की भावना को साकार करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'समाधान समारोह-2026' का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 21 अप्रैल से हुई है, जबकि इसका समापन 21, 22 और 23 अगस्त को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के साथ होगा।

मुख्यमंत्री साय ने बम्हनीडीह के विकास की नई यात्रा का किया शुभारंभ

रायपुर। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सबसे सशक्त कड़ी है और नगर पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं, बल्कि नागरिकों की आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने का प्रभावी माध्यम हैं। नवगठित नगर पंचायत बम्हनीडीह के प्रथम जनप्रतिनिधियों के कंधों पर केवल एक नगर के विकास की नहीं, बल्कि एक नई कार्यसंस्कृति और जनविश्वास की नींव रखने की जिम्मेदारी है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डडसेना एवं सभी पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें दायित्व सौंपा है, उसका प्रतिफल पारदर्शी प्रशासन, संवेदनशील कार्यशैली और विकास के रूप में दिखाई देना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बम्हनीडीह के विकास को नई गति देने वाली तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए दहिदा-बम्हनीडीह के बीच हसदेव नदी पर पुल निर्माण, बिजली विभाग का सब डिवीजन कार्यालय तथा सर्वसुविधायुक्त मंगल भवन के निर्माण की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आधारभूत संरचनाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधासंपन्न बनाना है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में विकास को नई गति देते हुए हर वर्ग के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को पक्के घर, किसानों को उनकी उपज का सम्मानजनक मूल्य, महिलाओं को महतारी वंदन योजना के जरिए आर्थिक संबल तथा युवाओं के लिए रोजगार और अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल बड़े शहरों के विकास से नहीं, बल्कि बम्हनीडीह जैसे उभरते नगरों को सशक्त बनाने से होगा। राज्य सरकार ऐसे सभी नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, बेहतर नागरिक सेवाओं और सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बम्हनीडीह नगर पंचायत जनभागीदारी, सुशासन और विकास का एक आदर्श मॉडल बनकर उभरेगी तथा आने वाले वर्षों में क्षेत्र की नई पहचान बनेगी। समारोह में कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक किरण सिंह देव ने भी जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह, नारायण चंदेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में पदोन्नति समेत लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

छत्तीसगढ़ के युवाओं को बड़ी सौगात 700 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती को मंजूरी

रायपुर। राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प और युवाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को नया कलेवर देने और सालों से अटके प्रशासनिक मामलों को सुलझाने के लिए आज उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए। प्रदेश के उच्च शिक्षा इतिहास में युवाओं के लिए इसे सबसे बड़ा दिन कहा जा सकता है। बैठक में सबसे बड़ा और अहम फैसला लेते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने सहायक प्राध्यापक के 700 रिक्त पदों पर अविलंब भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई रुकावट या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, विभाग के अन्य खाली पदों को भरने के लिए भी शासन को तत्काल नया प्रस्ताव भेजने का मार्ग

प्रशस्त कर दिया गया है। सीजीपीएससी (छत्तक्स्ट) के माध्यम से होने वाली प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य को भी अब युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।महाविद्यालयों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने कड़े लहजे में निर्देश दिया कि 31 जुलाई 2026 तक स्नातक प्राचार्यों की पदोन्नति का काम हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। नए शिक्षा सत्र में छत्तीसगढ़ का कोई भी स्नातक कॉलेज बिना नियमित प्राचार्य के नहीं रहेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार के एजेंडे में शिक्षा की गुणवत्ता सबसे ऊपर है। पदोन्नति का रास्ता साफ, कर्मचारियों और अतिथि प्राध्यापकों की सुनी गई मांग प्राध्यापकों और विभागीय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बैठक में कई संवेदनशील निर्णय लिए गए। पुराने नियम से मिलेगी तरक्की साल 2019 से पहले के बचे हुए सहायक प्राध्यापकों को 1990 के नियमों के तहत ही प्राध्यापक पद पर प्रमोट किया जाएगा, जिससे उनकी वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी। सहायक प्राध्यापकों के वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान की सूचियां लगभग तैयार हैं, जिन्हें जल्द ही जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से संघर्षरत अतिथि प्राध्यापकों की जायज मांगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेवा शर्तों में सुधार के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार तुरंत एक्शन लेने जा रही है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक ग्रेड-3 और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां अब 'राज्य कर्मचारी चयन आयोग' के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी। राज्य सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों के होनहारों के लिए एक अनोखी पहल की है। अब महाविद्यालयों में 90 घंटे, 90 दिन का विशेष अंग्रेजी संप्रेषण कोर्स चलाया जाएगा। इस अनूठे अभियान से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के भीतर का संकोच दूर होगा और वे देश-दुनिया के युवाओं के साथ कदम से कदम मिला सकेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में शासन के शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट प्रबंधन को लेकर मंत्री वर्मा ने वित्तीय शुचिता का संदेश देते हुए कहा कि विभाग में किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। अब किसी भी कॉलेज को बजट जारी करने से पहले प्रशासनिक अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।

महिला बाल विकास संचालनालय में फेरबदल

आईसीडीएस का प्रभार अपर संचालक अर्चना राणा को

रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालनालय स्तर में बड़ा फेरबदल हुआ है। नया कार्य विभाजन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। गुरुवार को संचालनालय इंद्रावती भवन से जारी आदेश में संचालनालय में विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों-कर्मचारियों का कार्य विभाजन आदेश जारी किया गया। आईसीडीएस शाखा का प्रभार अपर संचालक अर्चना राणा सेठ को सौंपा गया है। उप संचालक अभय कुमार देवांगन हटा कर की जगह युवानंद खुंटे, रजनीश कोरे की नियुक्ति की गई है। सहायक संचालक के रूप में समीर सोरभ और सनमान असरोरी कार्य करेंगे। सहायक कर्मचारियों में प्रीति साहू (पर्यवेक्षक), सौभाग्य कौशिक (पर्यवेक्षक), धीरज कुमार साहू (सहायक ग्रेड-01), सुषमा पैकरा (सहायक ग्रेड-02) एवं दुरूद साहू (सहायक ग्रेड-02) आईसीडीएस शाखा में शामिल किए गए हैं।

इसी तरह से मिशन वात्सल्य शाखा में अपर संचालक अर्चना राणा सेठ तथा उप संचालक नीलम देवांगन को जिम्मेदारी दी गई है।

सहायक कर्मचारी के रूप में विकास सिंह (सहायक ग्रेड-03) कार्य करेंगे। इसी प्रकार स्थापना/न्यायालयीन प्रकरण शाखा का प्रभार अपर संचालक अर्चना राणा सेठ के पास रहेगा। उप संचालक के रूप में श्रुति पी. नेरकर एवं ममता साहू तथा सहायक संचालक कनकवला राम होंगी। सहायक कर्मचारियों में जितेन्द्र कुमार ठाकुर (अधीक्षक), आनंदराव चौधरी (अधीक्षक), योगिता साहू (सहायक ग्रेड-02) एवं हेमलता अग्रवाल (पर्यवेक्षक)शामिल हैं।

प्रशिक्षण/जनसंपर्क शाखा की जिम्मेदारी अपर संचालक अर्चना राणा सेठ तथा उप संचालक युवानंद खुंटे को सौंपी गई है। सहायक कर्मचारी के रूप में ललित कुमार उइके (अधीक्षक)कार्य करेंगे। महिला सशक्तिकरण शाखा में संयुक्त संचालक सीएस लाल को जिम्मेदारी दी गई है। उप संचालक के रूप में आनंद प्रकाश कश्यप को सौंपा गया है जबकि आईसीडीएस शाखा से हटाकर अभय कुमार देवांगन महिला

विश्व खेल पत्रकार दिवस पर रायपुर प्रेस क्लब में खेल पत्रकारों का आत्मीय मिलन एवं सम्मान समारोह

रायपुर। विश्व खेल पत्रकार दिवस के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब द्वारा खेल पत्रकारों के सम्मान में आत्मीय मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खेल जगत की खबरों को जन-जन तक पहुँचाने वाले वरिष्ठ एवं युवा खेल पत्रकारों का सम्मान किया गया तथा खेल पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर सार्थक चर्चा हुई। समारोह के दौरान वरिष्ठ एवं युवा खेल पत्रकारों ने अपने-अपने दौर के यादगार, प्रेरक और चुनौतीपूर्ण अनुभव साझा किए। वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में भी मैदान से खबरें

जुटाकर उन्होंने खेल प्रेमियों तक सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाई। साथ ही खेल पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, नई तकनीकों और भविष्य की चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम में खेल पत्रकारिता जगत के अनेक वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित पत्रकार उपस्थित रहे। इनमें प्रमुख रूप से प्रशांत शर्मा, प्रकाश शर्मा, राजेश दुबे, विजय मिश्रा, डॉ. कमलेश गोगिया, शंकर चंद्राकर, पी. रामाराव नायडू, दिनेश कुमार, हेमंत डोंगरे, सुशील अग्रवाल, अख्तर हुसैन, पवन ठाकुर, अजय सक्सेना, स्टार जैन, प्रवीण सिंह, लवेंदर सिंघोत्रा एवं मनीष वोरा संतोष साहू जूनियर शामिल रहे।

चंगोराभाठा में शाला प्रवेश उत्सव, विधायक और महापौर बच्चों का किया स्वागत

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर जोन-5 अंतर्गत डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड क्रमांक 68 स्थित चंगोराभाठा की हरी ठाकुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी, रायपुर नगर निगम महापौर मीनल चौबे, पार्षद दुर्गा यादराम साहू सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर और पुष्प भेंटकर आत्मीय स्वागत किया। विद्यालय परिसर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया। बच्चों और शिक्षकों में कार्यक्रम को लेकर विशेष उत्साह रहा। इस अवसर पर

अतिथियों ने विद्यार्थियों को नए सत्र की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। विधायक सुनील सोनी और महापौर मीनल चौबे ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने परिश्रम और लगन से अच्छे अंक प्राप्त करें और अपने परिवार,

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल

जांच और पारदर्शिता की मांग तेज

रायपुर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अंबिकापुर में बीते मई महीने में संपन्न हुई प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया गंभीर आरोपों और विवादों के कारण एक बार फिर चर्चा में आ गई है। विश्वविद्यालय द्वारा 22 दिसंबर 2025 को सहायक प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के विभिन्न पदों के लिए जारी विज्ञापन के बाद कई अभ्यर्थियों, सामाजिक संगठनों और छात्र-युवा संगठनों ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं, नियमों के उल्लंघन और प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले आवश्यक रोस्टर निर्धारण समिति का गठन नहीं किया गया तथा विश्वविद्यालय में रोस्टर रजिस्टर का समुचित

संधारण भी नहीं किया गया। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह दावा किया गया है कि कार्यपरिषद की पूर्व स्वीकृति के बिना ही भर्ती विज्ञापन जारी किया गया, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े नियमों के अनुसार ऐसी स्वीकृति आवश्यक मानी जाती है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल कुछ विभागों और विषयों को लेकर भी अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि कुछ विषयों में पात्र अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया, जबकि पात्रता और अनुभव संबंधी मानकों की व्याख्या में असमानता बरती गई।

पर्यावरण विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, वानिकी तथा अन्य विभागों के कई अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन निरस्त किए जाने पर सवाल उठाए हैं। शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना है कि कुछ विभागों के नाम और विषय संयोजन पूर्व की भर्तियों से भिन्न रखे गए, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके अलावा विज्ञापन में संबद्ध विषयों (एलाइड सब्जेक्ट्स) का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण कई उम्मीदवारों को आवेदन और पात्रता निर्धारण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

21 से 23 अगस्त तक लगेगी विशेष लोक अदालत, लम्बित मामलों का होगा निपटारा

रायपुर। न्याय को सरल, सुलभ और आमजन तक पहुंचाने तथा आपसी सहभागिता और सहमति के माध्यम से न्याय की भावना को साकार करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'समाधान समारोह-2026' का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से हुई है, जबकि इसका समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के साथ होगा।

विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22 और 23 अगस्त को होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में लंबित मामलों को शामिल किया जाएगा। विशेष लोक अदालत से पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका, उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति स्थित मध्यस्थता केंद्रों में किया जाएगा। पक्षकार इन सुलह-प्रयास के लिए बैठकों एवं वार्ताओं में सशरीर अथवा आभासी (ऑनलाइन) रूप से शामिल हो सकते हैं। इस समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) के आयोजन का लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का सुलह एवं आपसी सहमति से निष्पादन करना है। अधिवक्तागण, वादकारियों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

साय के निर्देश, चौधरी की पहल पर शासकीय कर्मियों को बड़ी राहत

ई-कोष से जुड़ी डिजिटल व्यवस्था से कर्मचारियों को मिलेगा अल्पावधि ऋण

रायपुर। राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रारंभ की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं के समय त्वरित, सरल एवं पारदर्शी ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें असुविधाजनक अथवा अनौपचारिक वित्तीय स्रोतों पर निर्भर न रहना पड़े। यह सुविधा राज्य शासन की ई-कोष प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे कर्मचारियों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई और कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार शासकीय कर्मचारियों को आवश्यकता के समय कर्मचारियों को त्वरित, सरल और पारदर्शी वित्तीय सहायता उपलब्ध हो, इसी उद्देश्य से अल्पावधि ऋण सुविधा प्रारंभ की गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह

अल्पावधि ऋण सुविधा कर्मचारियों को आवश्यकता के समय त्वरित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी तथा उन्हें सम्मानजनक एवं सुविधाजनक वित्तीय विकल्प प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी एवं सुरक्षित है। कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर (Employee Corner) के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ऋण से संबंधित सभी शर्तें, ब्याज दर, ईएमआई, शुल्क तथा की फैक्ट स्टेटमेंट (Key Fact Statement-KFS) जैसी आवश्यक जानकारियां पहले से उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि कर्मचारी पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें।नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के उपरांत ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण तथा सहमति (Consent) की प्रक्रिया पूर्ण होने पर ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया त्वरित रूप से पूरी की जाएगी। ऋण की मासिक किस्तों का भुगतान वेतन से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure-SOP) के अनुसार पूरी व्यवस्था में डेटा सुरक्षा, गोपनीयता एवं डिजिटल प्रमाणीकरण के उच्च मानकों का पालन किया जाएगा। कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग केवल उनकी सहमति से किया जाएगा तथा सभी लेन-देन सुरक्षित डिजिटल माध्यम से संपन्न होंगे।

केंद्र प्रवर्तित योजना की राशि एजेंसियों या वेंडर्स को जारी न कर विभागों में जमा

रायपुर। वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों द्वारा बरती जा रही एक बड़ी अनियमितता पकड़ी है। वित्त के अनुसार विभाग केंद्र प्रवर्तित योजना की राशि एजेंसियों या वेंडर्स को जारी न कर अपने खाते में जमा (पार्किंग)कर रखें हैं।

विशेष सचिव वित्त शीतल शाश्वत वर्मा (आईआरएस) ने आज सभी एसीएस पीएस और सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत अपनी निधियों के जस्ट इन टाइम उपयोग तथा वास्तविक हितग्राहियों या वेंडर्स को समयबद्ध भुगतान के लिए एस?एन?ए स्पर्श के निर्देश राज्य में भी लागू हैं। वर्मा ने आदेश में कहा कि कतिपय विभागों के आंकड़ों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि कुछ राशियां वास्तविक वेंडर्स को हस्तांतरित होने के स्थान पर शासकीय एजेंसियों/विभागों के खातों में जमा की गई है।

ऐसे में विभाग के अधीन संचालित समस्त सीसीएस योजनाओं एवं एजेंसियों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि तीन वर्ष से लागू उक्त दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन हो तथा निधियों का उपयोग केवल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।

महत्वपूर्ण ख़बर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो

- स्पोर्ट्स न्यूज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यकीनन ग्रह पर सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं। पुर्तगाली फुटबॉल आइकन खेल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि वह अपने अंतिम स्वांसोंग के लिए तैयार हो रहे हैं। मार्का पर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रोनाल्डो मौजूदा फीफा विश्व कप 2026 के ठीक बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने जा रहे हैं। रोनाल्डो 41 साल के हैं और उनकी उम्र कम नहीं हो रही है। अगर रिपोर्ट सच निकली तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ था। रोनाल्डो की बहन ने ही इस कदम की पुष्टि की है. 'यह उनका आखिरी डांस है' स्पोर्ट टीवी से बात करते हुए, रोनाल्डो की बहन कटिया ने कहा, जब तक यह चले तब तक इसका आनंद लें।

महिला टी20 विश्व कप के लिए कंफर्म हुई टीमें

नई दिल्ली। महिला टी-20 विश्व कप 2026 रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ते हुए अब फाइनल मुकाबले तक आ पहुंचा है. टूनार्मेंट में हिस्सा लेने वाली कई 8 टीमों के साथ ही टीम इंडिया का सफर लीग स्टेज से ही खत्म हो गया था. हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी इस टूनार्मेंट के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी थी. मगर, अब सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा चुके हैं और फाइनलिस्ट टीमें कंफर्म हो गई हैं. तो आइए आपको बताते हैं कि फाइनल में कौन-कौन सी टीम पहुंची हैं और उनका सामना कब और कहां होगा.

कौन सी टीमें फाइनल में पहुंची?

12 टीमों वाला महिला टी-20 विश्व कप 2026 अब फाइनल मुकाबले तक आ पहुंचा है. पहला सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था, जिसमें 8 विकेट से जीत दर्ज करके कंगारू टीम ने फाइनल का टिकट कटा लिया था. तो वहीं, दूसरा सेमीफाइनल मैच मेजबान इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया. इस मुकाबले को 40 रन से जीतकर इंग्लैंड की टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों ने फाइनल तक का सफर तय किया है. गौर करने वाली बात ये है कि दोनों ही टीमें अब तक इस टूनार्मेंट में विजयरथ पर सवार हैं और एक भी मैच नहीं हारी हैं.

कब खेला जाएगा फाइल मैच?

महिला टी-20 विश्व कप 2026 का फाइनल मैच 5 जुलाई रविवार को खेला जाएगा. ये मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा. जहां, एक ओर होगी 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और उनके सामने होगी एक बार की चैंपियन मेजबान इंग्लैंड की टीम. इस बात में कोई शक नहीं है कि खिताबी मैच काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जो टीम जीतेगी वह विजयरथ पर सवार रहते हुए और ट्रॉफी जीतकर टूनार्मेंट का अंत करेगी. जबकि हारने वाली टीम के लिए ये टूनार्मेंट की पहली हार होगी.

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 42 टी-20 आई मैच खेले गए हैं. इसमें 24 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है, जबकि 17 मुकाबले में इंग्लैंड ने जीत अपने नाम की है. एक मैच टाई रहा है. हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. मगर, दोनों टीमों के बीच यकीनन फाइनल में एक कांटे की टक्कर वाला मैच देखने को मिलना तय है.

ऐसी हैं दोनों टीमें

इंग्लैंड महिला टीमः एमी जोन्स (विकेटकीपर), डैनी वायट-हॉज, सोफिया डंकले, एलिस कैपसी, हीथर नाइट, फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लेट डीन (कप्तान), सोफी एक्लेस्टोन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल, नैट साइवर-ब्रंट, टिली कोर्टीन-कोलमैन, लॉरेन फाइलर, इस्सी वोंग

ऑस्ट्रेलिया महिला टीमः जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), किम गार्थ, लुसी हैमिल्टन, मेगन शूट, अलाना किंग, ग्रेस हैरिस, ताहलिया मैकग्रा

नॉकआउट मैच जीतने के बाद रोनाल्डो ने क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी

जीत के बाद किया इमोशनल सेलिब्रेशन वायरल

पुर्तगाल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंडर ऑफ 32 में पुर्तगाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर जीत दर्ज कर ली है. इस मुकाबले में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का कमाल भी देखने को मिला जिन्होंने पेनल्टी मिलने पर अहम समय पर गोल किया. इस मैच को जीतने के बाद रोनाल्डो ने पूरे जोश के साथ सेलिब्रेशन किया और इस दौरान वह अपने आंसू नहीं रोक सके. इस मैच में रोनाल्डो अपनी नंबर-7 की नहीं बल्कि नंबर-21 की जर्सी पहनकर उतरे थे. इसके बाद से ही हर कोई जानना चाहता है कि आखिर रोनाल्डो ने नंबर-21 की जर्सी क्यों पहनी.

पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रोएशिया के खिलाफ फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मैच के बाद नंबर-21 की जर्सी पहनकर उतरे. उन्होंने अपने दिवंगत साथी डियोगो जोटा को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जर्सी पहनी. नंबर-21 जोटा की पुर्तगाल टीम में जर्सी थी. यह मैच जोटा की सड़क हादसे में मौत की पहली बरसी से ठीक पहले खेला गया था. पुर्तगाल की 2-1 की रोमांचक जीत के बाद रोनाल्डो भावुक हो गए और जोटा की नंबर-21 जर्सी पहनकर मैदान पर पहुंचे. यह उनके पूर्व साथी के प्रति सम्मान और याद का भावुक संदेश था, जिसने दुनियाभर के करोड़ों फुटबॉल फैंस का दिल छू लिया.

पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच एक कांटे की टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिला. इस मैच में दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत दर्ज करने में अहम भूमिका निभाई. पहले हाफ में क्रोएशिया और पुर्तगाल दोनों की ही तरफ से कोई गोल नहीं हुआ. फिर दूसरे हाफ की शुरूआत होने के बाद 53वें मिनट में क्रोएशिया के पेरिसिच ने गोल दाग दिया और उनकी टीम 1-0 से आगे हो गई. इसके बाद पुर्तगाल ने कमाल की वापसी की और 64वें मिनट में रोनाल्डो ने पेनल्टी गोल करके मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया. इसके बाद 8वें मिनट पर रोनाल्डो के सब्स्टिट्यूट के तौर पर रुबेन नेवेस मैदान पर आए.

वैभव सूर्यवंशी पर दिग्गज क्रिकेटर का बड़ा बयान

'ये बुरा हुआ, उसे मुश्किल में डालने...'

नई दिल्ली। भारत के 15 साल के युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैं और इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल तो किया गया लेकिन उन्हें अभी तक प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया है. वैभव को लगातार नहीं खिलाए जाने और उनका अंतरराष्ट्रीय डेब्यू नहीं कराने अब फैंस कप्तान श्रेयस अय्यर, हेड कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं. वैभव को टीम इंडिया में क्यों नहीं खिलाया जा रहा है. इस पर दुनिया भर का हर क्रिकेट दिग्गज अपनी राय दे रहा है.

भारत ने पहले आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज खेली. उस सीरीज के दोनों मैचों में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला. आयरलैंड के खिलाफ उनका डेब्यू बनता था. लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला. अब इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही हैं. इस सीरीज के पहले मुकाबले में भी उन्हें मौका नहीं मिला. अब आगे भी उनके प्लेइंग-11 में चांस मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं.

भारतीय कप्तान और टीम मैनेजमैंट वैभव सूर्यवंशी के प्लेइंग-11 में शामिल करने पर अजीबो-गरीब बयान देकर अपना फंदा छुटा रहे हैं. 15 साल के इस बच्चे को मौका नहीं देने से उनका आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ रहा होगा. अब उन पर साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने बड़ा बयान दिया है. डिविलियर्स ने वैभव को नहीं खिलाना टीम इंडिया का बड़ा बलंडर बताया है.

वैभव सूर्यवंशी पर एबी डिविलियर्स ने दिया बड़ा बयान

एबी डिविलियर्स ने कहा कि, 'उसे कब मौका मिलेगा? मुझे लगा कि आयरलैंड सीरीज वैभव सूर्यवंशी के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव लेने का सही मौका था. यह बुरा हुआ कि उसे कभी मौका नहीं मिला. मैं रयान टेन डोएशेट से सहमत नहीं हूं, जो कहते हैं कि वैभव को भी किसी दूसरे खिलाड़ी की तरह इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. आईपीएल के बाद उसे मुश्किल में डालने का समय आ गया था, खासकर आयरलैंड जैसी छोटी टीम के खिलाफ उसे नहीं खिलाना टीम इंडिया का बड़ा बलंडर था'.

कारोबार

व्हाट्सएप प्राइवेसी सेटिंग्स को लेकर लगातार हो रही सख्त

नई दिल्ली। जल्द ही व्हाट्सएप में ऐसा हो सकता है कि अगर किसी यूजर ने आपको ब्लॉक किया है, तो आपको इसका पता नहीं चल पाएगा।

व्हाट्सएप में यह नया अपडेट साफ तौर पर दशार्ता है कि कंपनी अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को लेकर लगातार सख्त होती जा रही है। व्हाट्सएप अपने करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में है। वर्तमान में यह फीचर टेस्टिंग फेज में है और अभी आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। कुछ समय पहले तक, तकनीकी विशेषज्ञों ने एक ऐसे तरीके का पता लगाया था जिसकी मदद से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि किसी कॉन्टैक्ट ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं। अब व्हाट्सएप इस ट्रिक को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अपने एन्क्रिप्शन सिस्टम में ऐसे बदलावों की टेस्टिंग कर रही है जिससे ब्लॉक करने वाले व्यक्ति की निजता को और भी बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा जा सके।

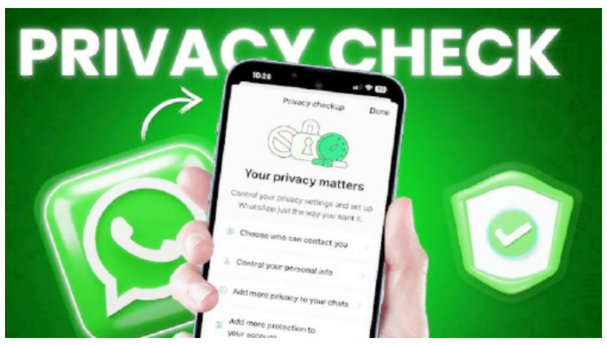

इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह उपयोगकर्ता हो या शोधकर्ता, तकनीकी तरीकों से यह पता न लगा सके कि उसे किसी ने ब्लॉक किया है या नहीं। यदि यह अपडेट सभी यूजर्स के लिए जारी होता है, तो पहले इस्तेमाल की जाने वाली ब्लॉक डिटेक्शन ट्रिक काम करना बंद कर देगी। हालांकि, आम व्हाट्सएप यूजर्स के लिए फिलहाल रोजमर्रा के अनुभव में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। चैटिंग, कॉलिंग, स्टेटस अपडेट और दूसरे फीचर्स पहले की तरह ही काम करते रहेंगे।

मुख्य अंतर केवल इतना होगा कि किसी ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं, इसको पुख्ता तौर पर कन्फर्म करना और भी मुश्किल हो जाएगा। व्हाट्सएप का मानना है कि किसी को ब्लॉक करना एक व्यक्तिगत फैसला है और इस निर्णय से जुड़ी जानकारी भी निजी ही रहनी चाहिए। अभी भी व्हाट्सएप पर ब्लॉक होने का कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की प्रोफाइल फोटो नहीं दिख रही है, लास्ट सीन नजर नहीं आ रहा है, मैसेज पर सिर्फ एक टिक आ रहा है या कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है, तो ये केवल संभावित संकेत हो सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चीज 100 प्रतिशत यह साबित नहीं करती कि आपको ब्लॉक किया गया है। नई टेस्टिंग और उसके बाद के अपडेट के बाद, ऐसे तकनीकी तरीकों से भी पुष्टि करना लगभग नामुमकिन हो सकता है।

विदेश में सफर होगा सफर, हवाई टिकट भी होंगे सस्ते

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आ रही लगातार गिरावट को देखते हुए एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है. एयरलाइन ने नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूनाइटेड किंगडम की उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज को कम कर दिया है. इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

कब और क्यों लागू हुआ फ्यूल सरचार्ज?

कंपनी ने बीते 7 अप्रैल को फ्यूल सरचार्ज लागू किया था, जब अमेरिका और ईरान में जंग के चलते पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर थी. उस दौरान होर्मुज की नाकेबंदी से दुनिया भर में क्रूड ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ा था. ऐसे में फ्यूल की बढ़ी हुई लागत और एयरस्पेस पर लगी पाबंदियों के चलते एयरलाइन का ऑपरेटिंग खर्च काफी बढ़ गया था. इसके चलते एयर इंडिया ग्रुप ने अपने ज्यादातर इंटरनेशनल रूट्स पर 24 से 280 अमेरिकी डॉलर के बीच फ्यूल सरचार्ज लगाने का ऐलान किया था. इस हिसाब से घरेलू यात्रियों से रूट के आधार पर 299 से 899 रुपये तक की फीस अतिरिक्त वसूली गई.

नए नियमः ईपीएफ में 1,800 रुपये से अधिक का अंशदान अब स्वैच्छिक

नई दिल्ली। वेतनभोगी कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी अंशदान ईपीएफ में करना होता था और कंपनी भी इतना ही अंशदान ईपीएफ में करती थी, लेकिन बीती 29 जून को श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 के तहत नए प्रावधान अधिसूचित कर दिए हैं। इस प्रावधान के तहत कर्मचारी भविष्य निधि में 15,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा से अधिक वेतन पर किए जाने वाले अंशदान को स्वैच्छिक बना दिया है। यानी 15,000 रुपये की वेतन सीमा के आधार पर निर्धारित 1,800 रुपये से अधिक का ईपीएफ अंशदान अब अनिवार्य नहीं होगा।

बाजार में तीसरे दिन भी तेजी, इन शेयरों पर रहेगी नजर

मुम्बई। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दो कारोबारी सत्रों की तेजी के बाद अब निवेशकों की नजर शुक्रवार के कारोबार पर है। गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी, वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत और कई बड़ी कंपनियों के पहली तिमाही के कारोबारी अपडेट ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बाजार लगातार तीसरे दिन भी तेजी का सिलसिला कायम रख पाएगा या मुनाफावसूली हावी रहेगी।

बाजार की दिशा तय करने में विदेशी संस्थागत निवेशकों की गतिविधियां, अमेरिकी बाजारों का रुख, कंपनियों के तिमाही अपडेट और कॉरपोरेट घोषणाएं अहम भूमिका निभाएंगी। हाल के दिनों में आईटी सेक्टर ने बाजार को मजबूत सहारा दिया है। इसके अलावा बैंकिंग, ऑटो और मेटल सेक्टर के कई शेयर भी निवेशकों की निगाह में हैं। यदि वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत जारी रहते हैं तो घरेलू बाजार में खरीदारी का माहौल और मजबूत हो सकता है। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 579 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 169 अंक मजबूत होकर बंद हुआ। अमेरिकी बाजारों में मजबूती और एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने घरेलू निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई, ब्याज दरों और वैश्विक आर्थिक हालात को लेकर फिलहाल बाजार में पहले जैसी चिंता नहीं दिख रही है।

अब भारत में मनमानी नहीं कर पाएंगी VPN कंपनियां, बात न मानी तो जेल जाएंगे अधिकारी

नई दिल्ली. भारत में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों और इसे प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार अब वीपीएन कंपनियों की लगाम कसने की तैयारी कर ली है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार एक ऐसा सख्त कानूनी ढांचा तैयार कर रही है, जिसके तहत विदेशी वीपीएन कंपनियों को न सिर्फ भारत में अपना परमानेंट ऑफिस खोलना होगा, बल्कि स्थानीय अनुपालन अधिकारियों भी नियुक्त करने होंगे. अगर कंपनियों ने सरकार के नियमों और निदेर्शों को मानने से इनकार किया, तो भारत में मौजूद उनके अधिकारियों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

वीपीएन कंपनियों पर सख्ती की वजह इन कंपनियों द्वारा सरकारी आदेशों का पालन न करन है. साल 2022 में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने एक निर्देश जारी किया था. इसके तहत वीपीएन कंपनियों के लिए अपने यूजर्स का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस जैसे

संवेदनशील डेटा को 5 साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया था. लेकिन, एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, प्रोटॉन वीपीएन और सर्फशार्क जैसी दिग्गज कंपनियों ने इसका विरोध किया और भारत से अपने फिजिकल सर्वर ही हटा लिए.

वीपीएन यूजर के असली क्ष्ठ एड्रेस को छिपा देता है और इंटरनेट ट्रैफिक को किसी दूसरे देश के सर्वर के जरिए रूट करता है. इससे ऐसा लगता है कि यूजर भारत में नहीं, बल्कि किसी और देश में बैठकर इंटरनेट चला रहा है. इसी बाईपास तकनीक के कारण सरकार द्वारा ब्लॉक की गई चीजें भी भारत में आसानी से खुल जाती हैं. पिछले कुछ समय में यह देखा गया है कि लोग वीपीएन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर उन वेबसाइट्स, ऐप्स और ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं, जिन्हें सरकार ने भारत में ब्लॉक किया हुआ है. इस साल NEET-UG SXe-टेस्ट से पहले सरकार ने अस्थायी रूप से टेलीग्राम को ब्लॉक किया था. उस दौरान प्रोटॉन वीपीएन के महाप्रबंधक डेविड पीटरसन ने खुलासा किया था कि भारत से उनके वीपीएन ऐप के रजिस्ट्रेशन में अचानक 120% से ज्यादा का उछाल आ गया था. बाद में सरकार ने उनका वह पोस्ट और अकाउंट दोनों भारत में ब्लॉक कर दिए थे.

महत्वपूर्ण ख़बर

मध्यप्रदेश में 2,548 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पदों पर होगी भर्ती

■ भोपाल। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर पोषण प्रबंधन को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 2,548 पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा रही हैं।

भर्ती में स्थानीय पात्रताधारियों को प्राथमिकता मिलेगी। कुल रिक्तियों में से 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकताओं के लिए और 1,767 पद आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।

एमपी ट्रांसको ने श्यामपुर में ऊर्जीकृत किया 50 एमवीए क्षमता का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर

■ भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने सीहोर जिले की पारेषण व्यवस्था को सुदृढता प्रदान करते हुए 132 केवी सब स्टेशन श्यामपुर की क्षमता वृद्धि की है। जहाँ 50 एमवीए क्षमता का एक अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर स्थापित कर उसे ऊर्जीकृत किया गया है।

स्कूल चलें अभियान के दौरान ही कराएं सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पणः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

होम गार्ड्स की कराएं भर्ती, अग्निवीरों को दिया जाएगा सुरक्षा बलों की नियुक्ति में आरक्षण

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य शासन की प्राथमिकता वाले विषयों पर त्वरित कार्यवाही की जाए। अभियान चलाकर लक्ष्य पूरे किए जाएं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन दिनों स्कूल चलो अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनि विद्यालय भवनों को लोकार्पण एवं स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सांदीपनि विद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा उत्कृष्ट नवाचार है। स्कूल शिक्षा विभाग इसकी राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए कार्य योजना तैयार करे। उन्होंने कहा कि चित्रकूट के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। यहां सती अनुसुईया मंदिर परिसर, सती अनुसुईया मल्टी फैसिलिटी सेंटर और गुप्त गोदावरी मंदिर परिसर का निर्माण होना है, यह काम तेजी से पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदाकिनी नदी जोड़ो परियोजना के लिए उत्तरप्रदेश सरकार तैयार है। जल्द ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में इस परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों (जैसे माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, दतिया, ओरछा, मैहर आदि) में धर्मशाला, सराय, अन्न क्षेत्र, प्याऊ, पेयजल टंकी, अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण के लिए धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। यह प्रोत्साहन रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान या अन्य रियायत स्वरूप में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को मंत्रालय में विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर विभागों की अद्यतन प्रगति एवं आगामी कार्य योजना (कार्यवाही) के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

भेल से भूमि वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से करें समन्वय

ग्रामीण क्षेत्रों आबादी की निःशुल्क रजिस्ट्री के लिए चलेगा अभियान

धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों पर धर्मशाला, सराय, अन्न क्षेत्र निर्माण के लिए

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव श्री मनीष रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला, अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे, अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन सहित अन्य प्रमुख सचिव एवं सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल के भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) को शासन द्वारा दी गई जमीन की भेल के लिए वर्तमान में अनुपयोगी भूमि उनसे वापस लेने के प्रयास किए जाएं। इसके लिए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय से समन्वय कर यह कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) की रासायनिक कचरे से मुक्त भूमि पर एक भव्य स्मारक का निर्माण होना है, इसके लिए एप्को कार्य योजना तैयार करे और वर्तमान में गुजरात के भुज में तैयार म्यूजियम का मौका मुआयना कर भोपाल में भी ऐसा ही भव्य स्मारक तैयार करने के लिए विधिवत प्रस्ताव दे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की निःशुल्क रजिस्ट्री के लिए राज्य के 53 हजार गांवों में अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए गाँव-गाँव शिविर लगाकर ग्रामीणों के पंजीयन किए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि घोषित करने की प्रकिया को और भी सरल बनाया जाए। ग्रीष्मकाल में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लिए पहले से बेहतर तैयारी कर ली जाए। इस वर्ष प्रदेश के किसी भी जिले में पेयजल परिवहन की स्थिति निर्मित नहीं हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में श्री महाकालेश्वर मंदिर की तरह होमगार्ड्स के पदों का सृजन किया जाए और मंदिर समिति के वहन पर इनकी नियुक्ति की जाए। अग्निवीरों को मध्यप्रदेश पुलिस में विशेष सशस्त्र बल (आरक्षक पद) की नियुक्ति में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपर मुख्य सचिव गृह को निर्देशित किया कि वे इस संबंध में अतिशीघ्र कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासन की व्यवस्था है कि सभी शासकीय सेवक कार्य दिवसों में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कार्यालय में रहकर अपने पदेन कार्य सम्पन्न करें। समय की पाबंदी सबके लिए जरूरी है। राज्य मंत्रालय, विध्याचल एवं सतपुड़ा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तय समय पर उपस्थिति एवं रवानगी के लिए बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभाग अपने-अपने स्कूल चला रहे हैं, इन सभी स्कूलों को युक्तियुक्तकरण किया जाए। सभी वर्गों के छात्रावासों को संयुक्त रूप से एक छात्रावास में परिवर्तित कर विद्यार्थियों को यहां रखा जाए। इससे उनमें समरसता का भाव विकसित होगा। इन्हें समरसता छात्रावास का नाम दिया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चित्रकूट एवं ममलेश्वर के विकास के लिए भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए वन भूमि का उपयोग कर लिया जाए। बताया गया कि इस कार्य के निमित्त भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राम वन गमनपथ परियोजना एवं श्रीकृष्ण पाथेय के निर्माण में तेजी लाएं और इसे समय-सीमा में पूरा करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन की दताना-मताना हवाई पट्टी के स्थान पर नवीन हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में शीघ्र कार्यवाही की जाए। प्रयास करें कि यहां जल्द से जल्द यहां भूमि-पूजन कर लिया लाए। बताया गया कि नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। इसके लिए धारा 11 की कार्रवाई भी की जा चुकी है। जल्द ही नवीन हवाई अड्डे निर्माण का भूमि-पूजन करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री होंगे नमन मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष

18 जिलों में होंगे नर्मदा जयंती कार्यक्रम, नदी संरक्षण से समाज को भी जोड़ें : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मां नर्मदा प्रदेश की 33 प्रतिशत से अधिक आबादी की जीवन रेखा है। यह आबादी नर्मदा नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्र पर ही निर्भर है। नर्मदा हमारी धार्मिक आस्था, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत की आधारशिला है। इसे हर तरह से निर्मल और अविरल बनाए रख कर नर्मदा परिक्रमा पथ को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नर्मदा जयंती पर विभिन्न आयोजन किए जायें। नर्मदा और इसकी सहायक नदियों सहित पूरे प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए समाज को विशेषकर युवाओं को जोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि अब हर महीने नर्मदा समग्र की बैठक में इस नदी क्षेत्र के विकास के निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में नर्मदा समग्र की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि माँ नर्मदा के विकास से जुड़ना एक पवित्र काम है। सभी विभाग के अधिकारी पूरे समर्पण से यह काम करें। उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा पथ को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त कर पथिकों के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाये और परिक्रमा मार्ग पर संकेतक (सूचना पट्टिकाएं) भी लगाए जाए। नर्मदा के तट पर स्थित सभी धार्मिक और पवित्र स्थलों को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर जहां मंदिर हैं वहां श्रद्धालुओं के लिए अन्न क्षेत्र भी स्थापित किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐसे स्थानों पर दीनदयाल रसोई प्रारंभ कराने की व्यवस्था भी कराएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव श्री मनीष रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला, अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे सहित अन्य प्रमुख सचिव एवं सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नर्मदा समग्र से समन्वय कर नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में स्थित सभी आश्रमों की सूचियां तैयार कर लें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को निर्देशित किया कि वे सामूहिक प्रयास कर किसानों को घाटी क्षेत्र में नकद फसलों की पैदावार लेने के लिए प्रेरित करें।

नर्मदा विकास के लिए पहले से विद्यमान 3 समितियों से भी लेंगे सहयोग

अमरकंटक में बनेगा जैव विविधता प्रबंधन संस्थान

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि नर्मदा नदी के सीमावर्ती प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती पर आयोजन किए जाएंगे। माँ नर्मदा की भव्य आरती, नृत्य, गायन, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने बताया कि माँ नर्मदा के जल को सदैव निर्मल और अविरल बनाये रखने के लिए विभाग द्वारा 'नमन मिशन' तैयार किया गया है। यह मिशन मां नर्मदा घाटी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्राधिकृत होगा। मुख्यमंत्री इस नमन मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मिशन की साधारण सभा के उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव इस मिशन के सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मिशन के सह-सचिव होंगे। मिशन को क्रियान्वित करने के लिए इस साल 2026-27 का रोडमैप भी तैयार कर लिया गया है।

एसीएस श्रीमती रस्तोगी ने बताया कि इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए पहले से विद्यमान 3 समितियों (मंत्रिमण्डल समिति, अन्तर्विभागीय कार्यकारिणी समिति, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति) का भी सहयोग लिया जाएगा। मिशन के संचालन में जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, नगरीय विकास, वन, पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, वित्त, पर्यटन, विधि, उद्यानिकी, मत्स्य, राजस्व, जनजातीय कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति, धर्मस्व, योजना एवं आर्थिकी सांख्यिकी एवं खनिज संसाधन विभाग सदस्य के रूप में तथा 10 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। इस फंड के लिए 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राज्य अनुदान की व्यवस्था का प्रस्ताव है। अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल ने बताया कि मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में जैव विविधता प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। इसके लिए 32 लाख रुपये का योजना प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में करीब 415 हैक्टेयर क्षेत्र में वन विभाग 2.70 लाख पौधे लगायेगा।

अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में नर्मदा घाटों को निर्मल बनाये रखने की व्यवस्था की जा रही है। नर्मदा कोष पोर्टल भी बनाया जा रहा है। नगरीय निकायों के सीएमओ को नर्मदा क्षेत्र के विकास के लिए नोडल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र के 21 नगरों में 35 एसटीपी तैयार किए जा रहे है। यह काम दिसम्बर 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर के विकास के लिए यहां स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (साडा) तैयार की जाएगी। पर्यटन विभाग ने जानकारी दी कि महेश्वर में 18 होमस्टे तैयार किए है और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 13 गावों में 79 होमस्टे तैयार किए गये हैं। बैठक में पर्यावरण, धर्मस्व, राजस्व, खनिज साधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, योजना आर्थिकी सांख्यिकी, एवं अन्य विभागों ने भी नर्मदा घाटी क्षेत्र में किए जा रहे काम की जानकारी दी।

निर्वाचन आयोग ने घोषित की विधानसभा उपचुनाव दतिया की तिथियां

कलेक्टर ने दिए निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश

भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2 जुलाई 2026 को दतिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 22 उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। जारी कार्यक्रम अनुसार 6 जुलाई को गजट नोटीफिकेशन होकर नामांकन भरने की आखिरी तिथि 13 जुलाई 2026 रहेगी। दिनांक 14 जुलाई को नामांकन की छंटनी एवं 16 जुलाई तक नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि रहेगी। दिनांक 30 जुलाई को मतदान होगा एवं 3 अगस्त को मतगणना की जायेगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री स्वप्निल वानखेड़े द्वारा निर्वाचन के संबंध में बैठक बुलाई गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मयूर खंडेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षय कुमार तेम्रवाल, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह कुशवाहा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मंजीत सिंह चावला, रिटर्निंग ऑफीसर एवं एसडीएम सुश्री सोनाली राजपूत सहित निर्वाचन कार्य से संबंधित सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वानखेड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के दतिया विधानसभा क्रमांक 22 में उप निर्वाचन होने से सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने निर्वाचन आयोग के निदेशों का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान बिना रिटर्निंग ऑफीसर की अनुमति के बिना राजनैतिक प्रचार-प्रसार रैली, जुलूस सभाएं प्रतिबंधित रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार जिले में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (ख) के तहत आदेश जारी कर समस्त शस्त्र लायसेंस निलंबित करते हुए लायसेंसी शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र संबंधित थानों में दिनांक 10 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिए है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वर्षा को ऋतु को देखते हुए समस्त 291 मतदान केन्द्रों पर जल भराव की स्थिति को पूर्व में ही जांच लिया जाये। किसी मतदान केन्द्र पर यदि कोई मरम्मत कार्य की आवश्यकता हो तो पूर्व में ही कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से संवेदनशील क्षेत्र में फोर्स मूवमेंट एवं फ्लैग मार्च निकालने की बात कही। रिटर्निंग ऑफीसर को कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वानखेड़े ने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से आयोग के निदेर्शानुसार दतिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 22 में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान कराने की बात कही।

78 कार्यालय सहायक ग्रेड- तीन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति

भोपाल। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल द्वारा मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कार्यालय सहायक ग्रेड-तीन के 78 प्रशिक्षुओं की नई भर्ती एवं नियुक्ति की गई है। नवनियुक्त सभी 78 कार्यालय सहायक ग्रेड-तीन प्रशिक्षुओं ने 29 मई को पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर, भोपाल में कार्यभार ग्रहण कर प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत उन्हें कंपनी के विभिन्न शहर एवं संचालन-संधारण वृत्तों में प्रशिक्षण के शेष मॉड्यूल पूर्ण करने के लिये पदस्थ किया गया है। इससे प्रशिक्षुओं को मैदानी स्तर पर कार्य का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा तथा वे भविष्य में अधिक दक्षता एवं प्रभावशीलता के साथ अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे। यह भर्ती कंपनी के मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे प्रदेश के योग्य एवं शिक्षित युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही कंपनी के विभिन्न कार्यालयों एवं क्षेत्रीय इकाइयों में मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाया गया है। कार्यालय सहायक ग्रेड-तीन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति से कंपनी की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक गति मिलेगी तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएँ उपलब्ध कराने में सहायता प्राप्त होगी।

24 अन्य जिलों में भी केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया जारी

सागर, मुरैना और ग्वालियर में आधार सेवा केंद्र प्रारम्भ

भोपाल। नागरिकों को आधार संबंधी सेवाएं अधिक सुगमता एवं दक्षता के साथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गुरुवार को प्रदेश के सागर, मुरैना और ग्वालियर में नए आधार सेवा केंद्र प्रारम्भ किए गए।

ग्वालियर आधार सेवा केंद्र का कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान और मुरैना आधार सेवा केंद्र का कलेक्टर श्री लोकेश जांगिड़ ने शुभारंभ किया।

नए आधार सेवा केंद्र मुरैना में जौरा रोड स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के पास, सागर में अशोक विहार कॉलोनी स्थित बीएमसी तिल्ली वार्ड के सामने और ग्वालियर में हर्षनगर, नई गोविंदपुरी मेन रोड पर संचालित किए गए हैं। ये केंद्र सप्ताह के सातों दिन कार्यरत रहेंगे। इन केंद्रों पर आधार नामांकन, जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक अद्यतन सहित विभिन्न आधार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं, सुलभ शौचालय और केंद्र प्रबंधक की व्यवस्था की गई है। साथ ही दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए पृथक सेवा काउंटर भी बनाए गए हैं।

प्रदेश में अब यूआईडीएआई द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, उज्जैन, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, भिंड, सागर और मुरैना सहित 12 जिलों में संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों पर सेवा प्राप्त करने के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। यूआईडीएआई राज्य कार्यालय, भोपाल के निदेशक श्री सुमित मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में आधार सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से 24 अन्य जिलों में भी नए आधार सेवा केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इन केंद्रों के प्रारम्भ होने से नागरिकों को अपने निकट आधार संबंधी सेवाएं उपलब्ध होंगी और समय एवं संसाधनों की बचत होगी।

उज्जैन का त्रिनेत्र मॉडल शहरों की सुरक्षा एवं स्मार्ट निगरानी व्यवस्था का बनेगा आधार

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में उज्जैन ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर गौरवपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में लागू किए गए एआई-आधारित एकीकृत निगरानी तंत्र त्रिनेत्र को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत प्रतिष्ठित स्वर्ण (गोल्ड) पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया। कलेक्टर श्री रौशन कुमार ने उज्जैन जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने इस उपलब्धि को मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन तथा सभी के सामूहिक प्रयास तथा निरंतर परिश्रम का परिणाम बताया।

सम्मेलन के पहले दिन देश के विभिन्न राज्यों के जिला प्रशासनिक अधिकारियों एवं राज्यों ने अपने-अपने ई-गवर्नेंस नवाचारों का प्रदर्शन किया। कलेक्टर एवं अध्यक्ष उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड श्री रौशन कुमार सिंह द्वारा ₹त्रिनेत्र₹ परियोजना का विस्तृत प्रेजेंटेशन किया गया, जिसे उपस्थित विशेषज्ञों एवं प्रतिनिधियों द्वारा अत्यधिक सराहा गया।

सम्मेलन के दूसरे दिन गुरुवार को आयोजित समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में तथा राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री प्रथम कौशिक, श्री पलाश शर्मा, श्री सचिन जैन एवं आईटी टीम उपस्थित रही।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, भारत सरकार और उज्जैन के त्रिनेत्र प्रोजेक्ट को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने के लिये शीघ्र ही एक एमओयू होगा। उज्जैन में विकसित इस स्वदेशी एआई मॉडल की सफलता एवं देशव्यापी अनुकरणीयता पर केंद्र सरकार की मुहर है – अब उज्जैन का ₹त्रिनेत्र₹ मॉडल देश के अन्य शहरों की सुरक्षा एवं स्मार्ट निगरानी व्यवस्था का आधार बनेगा। यह न केवल उज्जैन, अपितु संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है।

संपादकः अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती वाग, पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।